2019

नेशनल एसोशिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी)

समन्वयक का प्रतिवेदन

अक्टूबर 2018 – जून 2019

प्रतिवेदन अवधि के दौरान राज्यों में क्रियाएँ

श्रद्धांजलि

डेंकनाल, ओड़ीशा मे गत दिनो एक दुर्घटना मे 4 स्ट्रीट वेंडर असमय हमारा साथ छोड़ गए | नासवी परिवार इस घटना के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है|

नासवी कार्यकारिणी समिति की बैठक

समन्वयक का प्रतिवेदन

24-06-2019, राजीव नगर, पटना

नासवी **कार्यकरणी समिति के सदस्यो का हार्दिक अभिनंदन !**

गत कार्यकारिणी समिति की बैठक सितंबर 2018 में वार्षिक आमसभा के दौरान हूई थी | देश में आम चुनाव के कारण इस बैठक को आयोजित करने में थोड़ा विलंब हूआ है | चुनाव के बाद पुनः एक मजबूत सरकार के गठन से हम काफी आशान्वित हैं | गत दिनों ही स्ट्रीट **वेंडिंग को रोजगार की श्रेणी में रखकर आर्थिक सर्वेक्षण** की बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई है | यदपि इसके दूरगामी प्रभाव व परिणाम क्या होंगे यह एक विचारणीय विषय है परंतु तत्कालीन रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए |

गत आम सभा सभा की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा फुटपाथ विक्रेताओं की समस्याओं से अवगत होने के बाद वादा किया गया था कि समस्या के निवारण के लिए मंत्रालय की निगरानी में जल्द ही एक बैठक की जाएगी | दिनांक **8 फरवरी 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली** में मंत्रालय की तरफ से एक **राष्ट्रिय कार्यशाला** का आयोजन किया गया जिसमें पूरे देश के नगर विकास विभाग के मंत्री व अधिकारी एवं विभिन्न नगर निकायों के आयुक्त को आमंत्रित किया गया तथा वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई, उन्हें साथ ही उन्हें कानून को प्रत्यक्ष रुप से लागू करने के लिए एवं चल रही प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया | नासवी के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक मे भाग लिया एवं समन्वयक द्वारा एक प्रस्तुतीकरण भी किया गया |

हाल ही मे **25 फरवरी एवं 6th जून 2019** शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, स्ट्रीट वेंडिंग कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक **दिशा निर्देश** राज्यो को भेजा गया है जिसको लागू करने की **जिम्मेवारी राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन (NULM)** के महत्व पूर्ण घटक सपोर्ट अर्बन स्ट्रीट वेंडिंग (SUSV) को दी गई है|

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने **26 राज्यो के 60 शहरों मे** स्ट्रीट वेंडिंग कानून के वास्तविक क्रियान्वयन का वस्तुस्थिति समझने के लिए कई **टीम का गठन** किया है जो वर्तमान मे अलग अलग **शहरों का दौरा कर रही** है|

नासवी द्वारा **एफ एस एस ए आई** के साथ संयुक्त रूप से आयोजित **10th स्ट्रीट फूड फेस्टिवल** अत्यंत सफल रहा | इस अवसर पर विभिन्न सत्रो मे संवाद व कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमे सरकार के अन्य विभागो भी शामिल हूए| इसका प्रभावी असर यह हूआ की शहरी विकास विभाग के स्तर पर एक नीतिगत फैसले लिए गए | केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष **शहरी समृद्धि उत्सव** मनाए जाने का निर्णय हुआ जिसमे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना शामिल किया

गया | इस वर्ष देश के कई भागो मे शहरी समृद्धि उत्सव मनाया गया जिसमे **नासवी ने दिल्ली एवं बिहार** में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की |

स्वस्थ भारत यात्रा: इट राइट मेला - नासवी के पहल से फूड वेंडर्स की कार्यशैली में आ रही है अनोखा बदलाव, एफ एस एस ए आई के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्वस्थ भारत यात्रा के कार्यशाला में फूड वेंडर्स को अपने विचार रखने का अवसर मिला |

स्ट्रीट वेंडर्स दिवस की लोकप्रियता भी साल दर साल बढ़ रही है| कई राज्यो से वेंडिंग ज़ोन बनने एवं वेंडर्स को परिचय पत्र वितरण की खबरे लगातार आ रही है| **दिल्ली सरकार** ने भी बहू प्रतीक्षित **योजना 2019** मे पारित कर दी है| **पश्चिम बंगाल** मे भी काफी जद्दो जहद के बाद **नियमावली बनी** एवं कुछ जगहो पर टीवीसी की प्रक्रिया शुरू हुई है| मध्य प्रदेश मे शिकायत निवारण समिति का गठन हुआ है, अन्य राज्य मे प्रक्रिया जारी है| यदपि चुनौतिया अभी भी कम नहीं हुई है एवं प्रशासन का हथौड़ा चल ही रहा है|

स्ट्रीटनेट से कुछ सदस्य संगठनों के बाहर निकलने, और स्ट्रीटनेट में शासन के तरीके के बारे में अन्य संबद्ध संगठनों से आने वाले नकारात्मक तथ्यो ने हमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर और बाहर स्व-नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नए संगठन का गठन करने के लिए प्रेरित किया है। गत बैठक मे लिए गए निर्णय के आलोक मे **सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल** नामक इस नए संगठन को **स्पेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय** द्वारा अनुमोदित क़ानूनके तहत पंजीकृत करवाया गया है ।

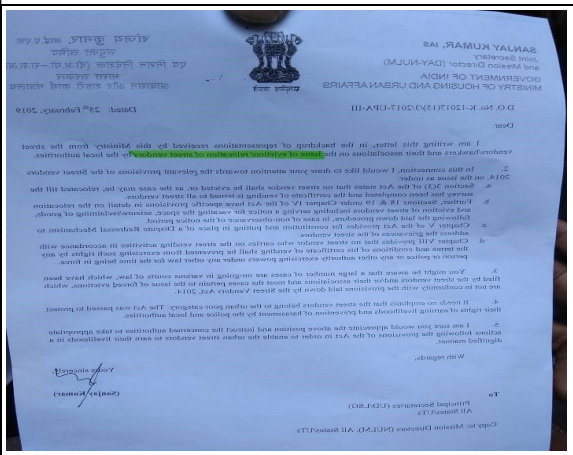

राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा राज्यवार कार्य के आधार पर अंक तालिका

उक्त अंक तालिका स्ट्रीट वेंडर्स कानून के अनुपालन के क्रम मे नियमावली एवं योजना के अधिसूचना जारी होने, स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण, टीवीसी का गठन, परिचय पत्र निर्गत, सिटि वेंडिंग प्लान, वेंडिंग ज़ोन का निर्माण एवं पुनर्स्थापन के आधार पर किया गया है|

S.No	State Name	Rank
1	Kerala	1
2	Andhra Pradesh	2
3	Gujarat	3
4	Chhattisgarh	4
5	Mizoram	5
6	Rajasthan	6
7	Madhya Pradesh	7
8	Arunachal Pradesh	8
9	Punjab	9
10	Himachal Pradesh	10
11	Jharkhand	11
12	Telangana	12
13	Maharashtra	13
14	Tripura	14
15	Chandigarh	15
16	Goa	15
17	Odisha	16
18	Tamil Nadu	17
19	Uttar Pradesh	18
20	Haryana	19
21	Bihar	20
22	Andaman & Nicobar Islands	21
23	Nagaland	21
24	Assam	22
25	West Bengal	23
26	Puducherry	24
27	Uttarakhand	25
28	Manipur	26
29	NCT of Delhi	26
30	Sikkim	26
31	Meghalaya	27
32	J& K	28
33	Karnataka	29

Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)

Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India

Systematic Progressive Analytical Real Time Ranking (SPARK) SPARK - SUSV

Sl.no	Name of state	Rules Notified	Scheme Notified	No of cities where Street Vendors Survey Completed Vs Total No. of Cities	No of ID card issued Vs No. of Street Vendors Identified	No of cities where TVC formed as per provision of Act Vs Total No. of Cities	No of cities in which city vending plan Completed Vs No. of Cities where TVC Formed	No of cities where Vendor Market Developed & functional Vs no of Cities	No of street vendors Trained Vs No. of ID cards Issued
1	Kerala	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Andhra Pradesh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Gujarat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Chhattisgarh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Mizoram	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Rajasthan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Madhya Pradesh	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8	Arunachal Pradesh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
9	Punjab	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
10	Himachal Pradesh	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
11	Jharkhand	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
12	Telangana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13	Maharashtra	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N
14	Tripura	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
15	Chandigarh	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
16	Goa	Y	Y	N	N	Y	N	N	N
17	Odisha	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
18	Tamil Nadu	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y
19	Uttar Pradesh	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
20	Haryana	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
21	Bihar	Y	Y	N	N	Y	N	N	N
22	Andaman & Nicobar Islands	Y	Y	N	N	N	N	N	N
23	Nagaland	Y	Y	N	N	N	N	N	N
24	Assam	Y	Y	N	N	N	N	N	N
25	West Bengal	Y	N	N	N	N	N	N	N
26	Puducherry	Y	N	N	N	Y	N	N	N
27	Uttarakhand	Y	N	N	N	N	N	N	N
28	Manipur	Y	N	N	N	N	N	N	N
29	NCT of Delhi	Y	N	N	N	N	N	N	N
30	Sikkim	Y	N	N	N	N	N	N	N
31	Meghalaya	N	N	N	N	Y	N	N	N
32	J& K	N	N	N	N	N	N	N	N
33	Karnataka	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N

राज्यवार स्थिति :

❖ दिल्ली

मैराथन प्रयास के बाद दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने 15 अप्रैल 2019 को राज्य योजना की अधिसूचना पारित किया | गत वर्ष 27 टीवीसी के सदस्यो का चुनाव हुआ था | परंतु लगभग 147 सदस्यो के रिक्तिया रह गई थी जिसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है एवं 30 जून की निर्वाचन की तारीख तय की गई है| गत वर्ष नव निर्वाचित टीवीसी सदस्यो का 4 बार ज़ोन वार प्रशिक्षण दिया गया|

दिल्ली में कई ऐसे रेहड़ी पटरी वालों का मार्केट जहां पर नगर निगम की मनमानी और पुलिस की दादागिरी के द्वारा अवैध रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए पूरे मार्केट को उजाड़ने की प्रयास को विफल किया गया | जो निम्नलिखित हैं लक्ष्मी नगर, मंडावली पुलिया सब्जी मंडी, शास्त्री पार्क , जामा मस्जिद, बदरपुर सब्जी मंडी , करोल बाग मार्केट, जनता कॉलोनी, न्यू उस्मानपुर घोंडा साप्ताहिक बाजार , भीखाजी कामा प्लेस |

15 अप्रैल 2019 को राज्य योजना की अधिसूचना पारित
TVC का गठन हेतु चुनाव 30 जून को पूरे होंगे
2018 मे 14 टीवीसी का चुनाव हुआ था
नासवी द्वारा टीवीसी सदस्यों का जोन वार प्रशिक्षण

नासवी के द्वारा दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट को चिन्हित किया गया जहां पर नगर निगम और पुलिस के द्वारा पथ विक्रेताओं का उत्पीड़न बदस्तूर जारी था अतः इससे छुटकारा पाने के लिए उन सभी मार्केट में नासवी के द्वारा पथ विक्रेता कानून जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक 2014 और संगठन की महत्व के बारे में रेहड़ी वालों को जागरूक करने के साथ-साथ उन को संगठित किया गया - जनता कॉलोनी वेलकम, रेहड़ी पटरी एकता मंच, फुटपाथी विक्रेता एकता मंच पुरानी सीमापुरी , घोंडा साप्ताहिक बाजार एकता मंच , फुटपाथी विक्रेता एकता मंच रहमान चौक खजूरी, रेहड़ी पटरी एसोसिएशन शालीमार बाग बुरारी, नत्थूपुरा फुटपाथ विक्रेता संगठन|

नासवी के द्वारा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को पत्र के द्वारा टाउन वेंडिंग कमिटी की नियमित मीटिंग कराने और फुटपाथी विक्रेताओं की गैर कानूनी बेदखली पर रोक लगाने के लिए पत्र के माध्यम से उनका ध्यान केंद्रीय किया गया |

टीवीसी सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्य योजना सह रणनीति): नासवी के द्वारा टाउन वेंडिंग कमिटी के सदस्यों को क्षमता वर्धक प्रशिक्षण देने के साथ साथ टीवीसी सदस्यों के द्वारा की जाने वाले कार्यों में आने वाली बाधाओं के समाधान और नगर निगम एवं राज्य सरकार के द्वारा की जा रही उपेक्षा से निपटने के लिए कार्य योजना सह रणनीति पर विचार विमर्श किया गया |

मानशरोवर पार्क के साप्ताहिक बाज़ार वाले वेंडर्स के समस्या को लेकर एडिशनल एसपी से मिला गया |

दिनांक 30 मार्च को दिल्ली में TVC के योजना व रणनीति बैठक में लिए गए निर्णय

1. चुनाव पूर्व एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से सभी नेताओ को संदेश देना की यदि वो वेंडर्स के मुद्दे पर संज्ञान नही लेंगे तो वोट का वहिष्कार किया जाएगा ।
2. DC के ऊपर TVC का बैठक करने एवं लिए गए निर्णय का अनुपालन करने हेतु दवाब बनाना।
3. पोलिटिकल पार्टी के मेनोफेस्टो में वेंडर्स के मुद्दे को जोड़वाना।
4. ग्रेवंश रिड्रेसल समिति के गठन के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखना एवं दवाव बनाना।
5. स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम बनाने हेतु दिल्ली सरकार को पत्र लिखना।
6. पुलिस कमिश्नर से मिला जाय एवं पुलिस की ज्यादती के बारे में बताया जाए एवं जब्ती राशिद की प्राप्ति की मांग की जाए।
7. सभी वेंडर्स से DC को पत्र लिखवाया जाय ताकि जल्द से जल्द वेंडर्स का रेगुलाशन किया जाय।

❖ उत्तरप्रदेश:

राज्य नियमावली व योजना दोनों ही बनी हुई है| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम एवं राज्य नियमावली के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया | कोर्ट ने उतरप्रदेश सरकार के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 15/6/2017 को नगर निकयाओ को लिखे गए पत्र के माध्यम से स्ट्रीट वेंडिंग कानून के प्रावधानों को नगर निकायो द्वारा लागू करने की अपेक्षा की | राज्य के कुल 17 नगर निकायो मे अभी तक 4171 स्ट्रीट वेंडर्स को विक्रय प्रमाण पत्र दिये गए है|

हापुड़ में नगर निगम और पुलिस दोनों के द्वारा फुटपाथी विक्रेताओं की दुकाने नहीं लगने दी जा रही थी जिसके फलस्वरूप वहां के फुटपाथी विक्रेता स्थानीय प्रशासन से दुकान लगाने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिए लेकिन स्थानीय निकाय और प्रशासन उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं थी तत्पश्चात फुटपाथ विक्रेता हाई कोर्ट में डीएम एसीपी और नगर निकाय को पार्टी बनाकर अपने अधिकार की मांग की जिसके फलस्वरूप हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हटाए गए फुटपाथी विक्रेता को उनको उसी स्थान पर व्यवस्थित कर दिया जाए और उनको रोजगार करने की अनुमति दी जाए| कोर्ट के आदेश के बाद सभी फुटपाथी विक्रेता अपनी दुकान लगाने लगे थे लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं उन लोगों को उस जोन में वेंडिंग करने नहीं दे रहे हैं इसके बाद फुटपाथी विक्रेता अपने स्थानीय एमएलए व एमपी से मिलकर भी इस मामले की शिकायत की लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है | अब वहां के फुटपाथ विक्रेता सीएम को पत्र के माध्यम से यह पूरे मामले से अवगत कराने की तैयारी में है |

आगरा में 4000 लोगों ने आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था | जिसमें दिनांक 3-04- 2019 सिर्फ 400 लोगों को नगर निगम के द्वारा आई कार्ड वितरण किया गया है बाकी दुकानदारो को इस

महीने के अंत तक आईडी कार्ड देने की नगर निगम की तैयारी है आगरा में अब तक टीवीसी की पांच बार बैठक हो चुकी है |

लखनऊ मे वेंडर्स की स्थिति मे लगातार परिवर्तन हो रहे है | बहुत कुछ माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर निर्भर हो गया है| पूर्व मे किए गए सर्वेक्षण को नगर निगम ने मानने से इंकार कर दिया| कोर्ट के पहल पर पुनः सर्वे करवाने की प्रक्रिया की प्रक्रिया शुरू की गई एवं कुल 8 जोन मे दिनांक 10 जून तक वेंडर्स से आवेदन मांगे गए| इस बीच निगम ने कुल 15122 पंजीयन पत्र वितरत किए जिसमे कुल 12311 लोगो ने ही आवेदन दिया| अब इसका सत्यापन किया जाएगा| मीडिया के खबरों एवं स्थानीय संगठनो के अनुसार कई बाहरी लोगो ने भी फॉर्म जमा किए है एवं वास्तविक वेंडर्स की संख्या 20 से 25 % ही है| नासवी कार्यकरणी सदस्य श्री गोकुल प्रसाद, पटरी दुकानदार कल्याण समिति एवं टाउन वेंडिंग समिति के सदस्य ने नगर आयुक्त सह अध्यक्ष टाउन वेंडिंग कमेटी एवं जिलाधिकारी को पत्र लिख कर विरोध दर्ज किया है| हालांकि लखनऊ नगर निगम ने अभी तक 200 से अधिक जगहो पर वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया है जिसमे लगभग 20 जगहो पर यातायात विभाग ने आपत्ति दर्ज की है | स्मार्ट सिटी एजेंसी ने कुल 168 जगह को वेंडिंग ज़ोन के लिए चिन्हित किया है|

पटरी दुकानदारों ने कर निरीक्षक को घेरा

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता
12-6-2019

फेरी नीति के तहत पंजीकरण फार्म जमा होने की अंतिम तारीख बीतने के बाद फार्म जमा करने पहुंचे पटरी दुकानदारों ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर हंगामा किया। जोन एक के कर अधीक्षक राजेश सिंह का घेराव किया। कोई सुनवाई न होने पर बुधवार को नगर आयुक्त से गुहार होगी।

दरअसल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम नई फेरी नीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। एक बार फिर पंजीकरण खोला गया। नए के साथ पूर्व में पंजीकृत पटरी दुकानदारों को भी फार्म जमा करने को कहा गया। एक से 10 जून तक का समय दिया गया। मंगलवार को जोन एक के कुछ पटरी दुकानदार फार्म जमा करने पहुंचे। लेकिन उनका फार्म जमा नहीं हो सका। इसपर वह हंगामा करने लगे।

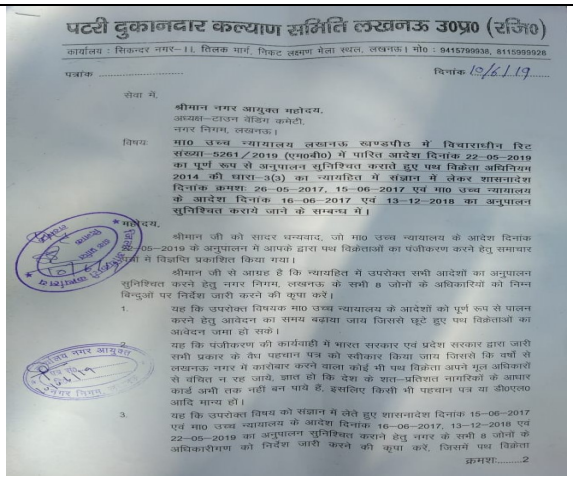

पटरी दुकानदार कल्याण समिति लखनऊ उ0प्र0 (रजि0)

कार्यालय : सिकन्दर नगर-11, तिलक मार्ग, निकट लक्ष्मण मेला ग्राउंड, लखनऊ। मो0 : 9415799938, 8115999926

दिनांक 10/6/19

सेवा में,

श्रीमान नगर आयुक्त महोदय,
अध्यक्ष—टाउन वेंडिंग कमेटी,
नगर निगम, लखनऊ।

विषय: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में विचाराधीन रिट संख्या—5261/2019 (एम0बी0) में पारित आदेश दिनांक 22-05-2019 का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की धारा-3(3) का न्यायादेश में संज्ञान में लेकर शासनादेश दिनांक क्रमशः 26-05-2017, 15-06-2017 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-06-2017 एवं 13-12-2018 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान जी को सादर धन्यवाद, जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-05-2019 के अनुपालन में आपके द्वारा पथ विक्रेताओं का पंजीकरण करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया।

श्रीमान जी से आग्रह है कि न्यायहित में उपरोक्त सभी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम, लखनऊ के सभी 8 जोनों के अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर निर्देश जारी करने की कृपा करें।

1. यह कि उपरोक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों को पूर्ण रूप से पालन करने हेतु आवेदन का समय बढ़ाया जाय जिससे छूटे हुए पथ विक्रेताओं का आवेदन जमा हो सके।
2. यह कि पंजीकरण की कार्यवाही में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार के वैध पहचान पत्र को स्वीकार किया जाय जिससे कि वर्षों से लखनऊ नगर में कारोबार करने वाला कोई भी पथ विक्रेता अपने मूल अधिकारों से वंचित न रह जाये, ज्ञात हो कि देश के शत-प्रतिशत नागरिकों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाये हैं, इसलिए किसी भी पहचान पत्र या ओ0एस0 आदि मान्य हो।
3. यह कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए शासनादेश दिनांक 15-06-2017 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-06-2017, 13-12-2018 एवं 22-05-2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नगर के सभी 8 जोनों के अधिकारीगण को निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिसमें पथ विक्रेता

क्रमशः.....2

- ग़ाज़ियाबाद नगर निगम के पंजीकृत पटरी दुकदारों को टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है|
- हापुर एवं मेरठ मे यदपि हालात चिंताजनक है|

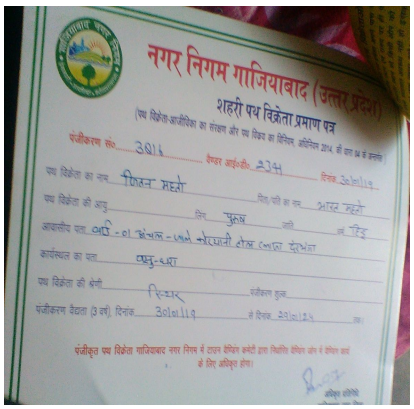

नगर निगम गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

शहरी पथ विक्रेता प्रमाण पत्र

नासवी एक परियोजना के अंतर्गत अदिति के सहयोग से **वाराणसी** मे कार्य कर रही है जहां निम्न कार्य किए गए है-

- 24 मार्केट कमिटी का गठन।
- 180 वेण्डर्स को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया।
- शहर स्तरीय संघ का गठन।
- जिला स्तरीय कॉ - ऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रगति में हैं।
- वेण्डर्स दिवस 20 जनवरी 2019 को मनाया गया जिसमें वेन्डर्स को 2014 के स्ट्रीट वेन्डर्स कानून एवम मार्केट कमिटी का लाभ बताया गया।
- स्ट्रीट वेण्डर्स का डाटा बेस बनाया जा रहा है।
- स्ट्रीट वेण्डर्स को जगह जगह पर नगर निगम से कचरा पेटी दिलाया गया।
- तीन स्थानों पर वेंडिंग जोन का कार्य प्रगति पर हैं।
- स्ट्रीट वेण्डर्स कानून को लागू करने के लिए माननीय स्थानीय विधायक से अपील की गई।
- वाराणसी मे ही दिनांक 17 जून 2019 को नगर विकास मंत्री के द्वारा नगर निगम के 5 ज़ोन के एक एक वेंडिंग जोन से कुल 250 पटरी दुकानदारो को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया| नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने कहा की वेंडर्स को एक क्रम मे रहने, गंदगी नहीं फैलाने व स्वास्थ्य व स्वक्क्क्षता के ध्यान देने की बात कही |

- मार्केट कमेटी के सदस्यो का नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया |
- राज्य नियमावली का संक्षेपन कर वेंडर्स को जागरूक किया गया|
- सरकारी योजनावों से वेंडोर्स को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है एवं जहां जरूरत है वहाँ वेंडर्स को मदद भी किया जा रहा है|
- वेण्डर्स के अधिकार के लिए 800 वेण्डरों का हस्ताक्षर अभियान कराया गया।
- नगर निगम मे वेन्डिंग ज़ोन की सूची जमा की गई।
- सर्वेक्षित वेंडर्स को पहचान पत्र दिलाने के लिए लगातार निगम पर दवाब बनाया जा रहा है|

लखनऊ, *मेरठ, गाज़ियाबाद, वाराणसी , आगरा,इलाहाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर* ***समेत कुल 14*** *नगर निकायो मे 1.96 लाख स्ट्रीट वेंडोर्स को परिचय पत्र दिया जाने हेतु चिन्हित किया गया है | वेंडिंग गतिविधियों के लिए SUDA द्वारा निकले गए टेंडर मे नासवी ने भी अप्लाई किया था लकीन तकनीकी कारणो से हमारा चुनाव नहीं हो सका था|*

❖ मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश मे रूल्स एवं स्कीम बन गया है| TVc का भी गठन किया गया है| ग्वालियर मे 12000 दुकानदारो का सर्वे हुआ है, परंतु अभी परिचय पत्र नहीं मिला है | 7 वेंडिंग जोन बनाये गए है 5 वेंडिंग जोन में कुछ दुकानदार बैठे है जबकि 2 वेंडिंग जोन में कोई नहीं बैठा है| पिंटू पार्क में 450 लोग चोपटी में 36 दुकानदार, फूलबाग में 34 , बिरला नगर में 150 , कम्पू में 18 दुकानदार एवं 244 दुकानदारो का जगह बनाया गया है| हजीरा हनुमान टॉकीज लस्कर **महिला वेंडिंग जोन** है जिसमे कोई नहीं बैठा है|

भारत सरकार के आदेश अनुसार शहरी विकास मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों ने देश के सभी राज्यों के नगरी प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कानून का निरीक्षण करने के लिए जबलपुर शहर आकर पथ विक्रेता नगर विक्रय समिति नगर निगम जबलपुर के सभी सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया बैठक में विस्तारपूर्वक जबलपुर शहर में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कानून एवं मध्य प्रदेश पथ विक्रेता अधिनियम 2017 नियम पर चर्चा की गई बैठक में पथ विक्रेता नगर विक्रय समिति नगर निगम जबलपुर के सदस्य बसंत शिवाजी पटेल रमाशंकर गुप्ता पार्वती वर्मन दुर्गाबाई काछी अशोक जयसवाल गोपाल चक्रवर्ती सुरेश पटेल विनीता चक्रवर्ती राजाराम अहिरवार सुशील पटेल अर्जुन लोधी आदि लोगों ने बैठक को संपन्न किया

साप्ताहिक बाजार का लाइसेंस जारी नहीं होने तक बेदखल करने का विरोध

फुटपाथी व्यापारियों ने किया निगम का घेराव, भागीदार बनाने की मांग

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

स्मार्ट सिटी के नाम पर बेदखल किए जाने से नाराज फुटपाथी व्यापारियों ने सोमवार को नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। मप्र असंगठित कामगार कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्र हुए फुटपाथी व्यापारियों ने निगम का घेराव कर व्यवस्था को जमकर कोसा। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की यह मांग थी कि भारत सरकार द्वारा 2014 में जारी किए गए अधिनियम पर अमल कर नगर निगम कमिश्नर की अध्यक्षता में नगर विक्रय समिति का गठन किया जाए। जिसमें 40 फीसदी भागीदारी फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों की हो। विक्रय समिति की अनुशंसा पर ही सर्वे कर विक्रय स्थान निर्धारित किए जाए और जब तक इसका सर्वे नहीं हो जाता, फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले वालों और साप्ताहिक बाजार का लाइसेंस जारी नहीं हो जाता जब तक उन्हें व्यापार करने से बेदखल न किया जाए।

विक्रय समिति गठित करने को लेकर प्रदर्शन करता मप्र असंगठित कामगार संघ।

गेट में धक्का देकर घुसे प्रदर्शन कर रहे फुटपाथी व्यापारी, गार्ड रोकने में रहे नाकाम

दोपहर करीब डेढ़ दर्जन सैकड़ों फुटपाथी व्यापारी नगर निगम पहुंचे। उन्हें देख नगर निगम के गार्ड मुख्य गेट पर ताला लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन व्यापारी गेट में धक्का देकर भीतर घुस गए। प्रदर्शन करने पहुंचे व्यापारियों की संख्या के आगे नगर निगम के गार्डों की एक न चली और व्यापारी नगर निगम के अंदर जा घुसे।

महापौर-कमिश्नर को ज्ञापन देने आधे घंटे तक अड़े रहे, की नारेबाजी

फुटपाथी व्यापारी मांगे का ज्ञापन महापौर और नगर निगम कमिश्नर को देना चाह रहे थे, लेकिन वे नहीं पहुंचे। फुटपाथी व्यापारी भी महापौर-कमिश्नर को ज्ञापन देने ऑफिस के सामने डटे रहे और नारेबाजी करते रहे।

करीब आधे घंटे बाद आए अपर आयुक्त

करीब आधे घंटे बाद अपर आयुक्त आरके शर्मा पहुंचे और ज्ञापन लिया। मप्र असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जल्द समिति गठित करने और पथ विक्रेताओं को विस्थापित करने से 30 दिन पहले नोटिस देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दुर्गा काछी, विनिता चक्रवर्ती, ममता काछी, सीमा झारिया, कौशल्या बर्मन सहित बड़ी संख्या में महिला विक्रेता मौजूद रहीं।

भोपाल: रूल्स एवं स्कीम है और TVC का गठन नॉमिनेट के द्वारा किया गया है चुनाव बाद इलेक्टेड होगा जबलपुर में भी TVC का गठन हुआ है| प्रदेश में कुल 52 जिला है 7 - 8 संभाग पथ विक्रेता शिकायत निवारण समिति बनेगी | 5 जिला मिलकर एक संभाग बनाया गया है| एक संभाग में भोपाल नगर निगम, शिहोर नगर निगम, विदिशा नगर निगम, रायगढ़, और रायसेन में पथ विक्रेता शिकायत निवारण समिति की गठन की गयी है जिसका सदस्य गोपाल सिंह लोधी एवं रत्नेश उपाध्याय है|

जबलपुर संभाग- जबलपुर संभाग में भीलवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बिगबोरी, शहडोल, बालाघाट, शिवानी, **नरसिंघ पुर** मे पथ विक्रेता शिकायत निवारण समिति गठित है|

❖ झारखंड

झारखंड राज्य सरकार ने 2015 में स्ट्रीट वेंडिंग नियमावली बनाए , हालांकि कुछ स्ट्रीट वेंडरों ने संगठित होकर संशोधन की मांग उठाई, फिर संशोधित नियम सितंबर 2016 में पारित किए गए और एक साल बाद 2017 में योजना को पारित किया गया। राज्य में अधिनियम को लागू करने के लिए तीन एजेंसियों का चयन किया गया है , सम्मन फाउंडेशन, एनएफ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और हरियाणा नुव युवक कला संगम।

सभी प्रमुख 44 यूएलबी ने नियमानुसार टीवीसी का गठन किया। हालाँकि, अधिकांश ULB में उचित तरीके से TVC की बैठकें नहीं हो सकीं। स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण पूरे शहर में एक वेब सक्षम सर्वेक्षण एप्लिकेशन ऐप के साथ पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण में शामिल किए गए कुल 37,701 स्ट्रीट वेंडरों में से लगभग 17000 विक्रेताओं को पहचान पत्र मिले। हालांकि, कुछ विक्रेताओं को छोड़ दिया गया है जो एनयूएलएम अधिकारी के अनुसार दूसरे चरण में शामिल होंगे। बाकी आईडी कार्ड वितरण जारी है। वेंडिंग जोन की पहचान की गई है।

रांची में एक वेंडिंग जोन बनाया गया है जहां 427 स्ट्रीट वेंडर्स को शिफ्ट किया गया है। बाकी शहरों में वेंडिंग ज़ोन के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की गई है।

मधेपुर एवं देवघर मे नगर निकायो के साथ बैठक की गई है एवं वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स संगठनो को खोज कर नासवी से जुडने के लिए प्रेरित किया गया है|

धनबाद मे स्ट्रीट वेंडर्स को कानून एवं राज्य नियमावली की प्रति भेज कर मदद की गई है|

जमशेदपुर - अदिति के सहयोग से एक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है|

- 11 मार्केट कमिटि का गठन ।
- 678 वेण्डर्स कार्ड वितरण ।
- नया वेण्डर्स कार्ड का आवेदन ।
- असंगठित श्रामिक कार्ड का आवेदन लिया गया एवं नगर निगम मे जामा करवाया गया
- मान–धान योजना का आवेदन जमा करवाया जा रहा है ।
- जिला स्तरीय पर कॉ-आपरेटिव का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रगति मे है ।
- वेण्डर्स दिवस मनाया जिसमे वेण्डर्स को 2014 के स्ट्रीट वेण्डर्स कानुन एवम मार्केट कमिटि का लाभ बताया गया।
- स्ट्रीट वेण्डर्स का डाटा बेस बनाया जा रहा है ।
- स्ट्रीट वेण्डर्स को नगर निगम से से जगह जगह पर कचरा पेटी दिलाया गया ।
- स्ट्रीट वेण्डर्स कानून को लागु करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय रधुवर दास से अपील कि गई गयी।
- नगर पालिका से एवम नगर निगम से वेण्डिग ज़ोन कि सूची जमा कि गई है
- लोन मेला मे स्ट्रीट वेण्डर्स को लोन दिलाया गया ।

झारखण्ड स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन जमशेदपुर के सदस्यों का नेतृत्व विकास एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे श्री राकेश त्रिपाठी ने 57 स्ट्रीट वेंण्डरो को प्रशिक्षित किया

15-05-2019 को बाराद्वारी मे मार्केट कमिटि का गठन किया गया। इस मार्केट कमिटि के गठन मे बाराद्वारी के 167 स्ट्रीट वेंण्डर्स उपस्थित हुए। चुनाव के मध्यम से मार्केट कमिटि के सद्स्यो का चुनाव किया गया।

टिनप्लैट में वेंडिंग ज़ोन बन कर तैयार है। जल्द ही वेण्डरो को यहाँ शिफ्त करने कि तैयारी की जा रही है । यहाँ कुल 92 दुकाने बन कर तैयार है, और 50 दुकाने बननी है।

जुबली पार्क में वेंडिंग जोन निर्माण हेतु नक्शा बनाया जा रहा है|

JNAC में CMMU के साथ बैठक की गई| बैठक मे टिनप्लेट के 50 फुटपाथी दुकानदार जिसे नव निर्मित वेंडिंग जोन मे जगह नही दी गई है, उनको दिलाने हेतु सुची सहित आवेदन दिया गया | सिटी मिशन मैनेजर आवेदन लिया और कहा की जल्द ही इन सभी फुटपाथी दुकानदारों वेंडिंग जोन में जगह दी जायेगी ।

जुबिली पार्क के पास बने वेंडिंग जोन का मुआयना किया

जमशेदपुर : जुबली पार्क के बगल में बने वेंडिंग जोन का कल जेएनएसी, संबंधित एजेंसी एवं स्ट्रील वेंडर यूनियन के प्रतिनिधियों ने स्थल मुआयना किया. इस दौरान वेंडिंग जोन निर्माण हेतु उसका नापी किया गया. मौके पर उपस्थित जेएनएसी के सिटी मिशन मैनेजर संजीत कुमार साहु, एनएफ इंफ्राटेक से सिटी प्लानर सबीर कुमार एवं झारखंड स्ट्रीट वेंडर यूनियन से अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव और अदिति संस्था से प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर अजीत कुमार और मोबलाइजर मनोज कुमार आदि मौजूद थे. सभी ने वेंडिंग जोन के लिए बने बाड़े एवं परिसर का मुआयना किया. उम्मीद की जा रही है कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को जल्द वहां शिफ्ट किया जाएगा.

टेल्को मार्केट में वेण्डर पहचान पत्र वितरित किये गये और साथ ही नये वेण्डर पहचान पत्र का आवेदन के लिये जरुरी कागजात जमा लिये गये।

❖ बिहार

राज्य सरकार ने फरवरी 2017 मे नियमावली व को योजनाओं को अधिसूचित किया है| बिहार में 142 नगर निकाय है एवं सभी मे टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन कर लिया गया है। 53 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण किया गया है। कुल 59501 वेंडर का सर्वेक्षण हुआ है जिसमे अभी तक कुल 12820 आईडी कार्ड वितरित किए गए है । राज्य में 346 वेंडिंग क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं| टीवीसी द्वारा 213 वेंडिंग जोन को मंजूरी दी गई है। कई जगह पर वेंडिंग जोने बनाने की प्रक्रिया चल रही है । ULB द्वारा स्थापित 67 वेंडिंग जोन बोर्ड लगाया गया है । भागलपुर मे सिटि वेंडिंग प्लान बना कर सरकार को नासवी द्वारा दिया गया है जिसके आधार पर विभाग द्वारा कई शहरी का वेंडिंग प्लान बनाने का निर्देश दिया है| 11 नगर निकायो से 27 वेंडिंग ज़ोन बनाने का प्रस्ताव सरकार को आए है| जिसमे 15 वेंडिंग जोन का प्रस्ताव को UD & HD बिहार द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं कुल 6,16,51,600 फंड आवंटित किए गए है | पटना मे ही 3 वेंडिंग जोन बनानये जा रहे है|

राज्य स्तरीय सहकारी को मजबूत बनाना: बिहार राज्य फूटपाथ दुकानदार सहकारी समिति का पंजीकरण अधिनियम 1996 के तहत किया गया है। हम सहकारी समिति के बोर्ड कि नियमित बैठक करते हैं और कई प्रस्तावों को मंजूरी देते हैं। बोर्ड ने विभिन्न जिले, जैसे पटना, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा, मोतिहारी, मधेपुरा और शेखपुरा में सहकारी के 7 केंद्र खोलने का निर्णय लिया। अभी हमने पटना और भागलपुर से शुरुआत की। पटना में सहकारी का एक केंद्रीय खाता खोला गया है जो सहकारी समिति के सीईओ और अध्यक्ष द्वारा संचालित है। हम स्ट्रीट वेंडोर्स को समिति की सदस्यता लेने के लिए जागरूक करते हैं। पटना में 91 स्ट्रीट वेंडर्स और भागलपुर में 147 स्ट्रीट वेंडर्स ने सहकारिता की हिस्सेदारी और भुगतान किया।

आधुनिक पुशकार्ट: - नासवी ने पटना में एक कंपनी "स्वस्तिक आर्ट एंड क्रिएशन" के साथ सहयोग किया, हम इस कंपनी को सब्जियों, फलों और खाद्य विक्रेताओं के लिए भी अलग-अलग प्रकार की पुश कार्ट तैयार करने में संलग्न किया हैं। कंपनी ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कई दौर की चर्चा के बाद विभिन्न प्रकार के पुश कार्ड डिजाइन किए। अंत में वे 2 आधुनिक पुश कार्ट का निर्माण कर रहे हैं जिसे स्ट्रीट वेंडर द्वारा स्वीकार किया गया था। इन गाड़ियों में लाइट, स्टोरेज, अलग सेक्शन, आधुनिक व्हील और जरूरत पड़ने पर वॉश बेसिन और पानी की व्यवस्था भी शामिल है। यह पुश कार्ट मजबूत, टिकाऊ और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसान होते हैं। इन गाड़ियों की कीमत 33,000 से 40,000 है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए EMI पर भी उपलब्ध है। अप्रैल मई के महीने में, इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा |

नेतृत्व विकास प्रशिक्षण: भागलपुर में 22/1/2016 को, नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 150 स्ट्रीट वेंडरों ने भाग लिया था। स्ट्रीट वेंडर्स के नेताओं को लीडरशिप क्वालिटी और कानूनी मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया था जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के कार्यान्वयन पर केंद्रित थे। नगर आयुक्त श्री श्याम बिहारी मीणा ने प्रशिक्षण का उद्घाटन किया और बातचीत कौशल पर एक व्याख्यान भी दिया। प्रशिक्षण को विभिन्न सत्रों में विभाजित किया गया था जैसे कि नेतृत्व का प्रकार, नेतृत्व की गुणवत्ता, प्रेरणा और स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम और नियम। प्रतिनिधियों के बीच एक पैम्फलेट भी वितरित किया गया।

राजगीर मे वेंडर्स को आईडी कार्ड वितरण : 8 वर्षो के निरंतर संघर्ष के बाद अन्तराष्ट्रिय पर्यटन स्थल राजगीर मे फूटपाथ दुकानदारो को नगर पंचायत द्वारा नियमन हेतु सर्वेक्षण कर 350 फूटपाथदुकानदारो को पहचान पत्र दिया गया |

Registration Certificate
Refer Regulation 2.1.1(5)
Government of Bihar
Department of Health and Family Welfare
State Food Safety Authority
Registration under FSS Act, 2006

पंजीकरण संख्या / Registration No. 20419001000304

1. खाद्य व्यापार ऑपरेटर का नाम और रुपयी पता / Name and permanent address of Food Business Operator (FBO) — PROP:- MOHAN PRASAD YADAV S/O GANAURI PRASAD AT:- MORYA LOK, GATE NO.- 1, Patna Sadar, Patna (Bihar), - 800001
2. स्थान का पता जहां खाद्य व्यापार / परिसर है / Address of location where food business is to be conducted / premises — M/S KALKATA KA MUNG DALL KA CHILLA, AT:- MORYA LOK, GATE NO.- 1, Patna Sadar, Patna (Bihar), - 800001
3. कारोबार का प्रकार / Kind of Business — Hawker Food stalls/arrangements in Religious gatherings, fairs etc
4. फोटो पहचान पत्र (विवरण) / Photo Identity Card — Aadhaar Card
5. यह पंजीकरण खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञा दी गई और यह अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन है जिनका अनुपालिकाएँ द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए / This Registration Certificate is issued under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the petty food business.

स्थान / Place : Patna
दिनांक / Date : 07/03/2019
वैधता अवधि / Period of Validity 06/03/2020

Stamp and signature of Registering Authority

विधिमान्यता और नवीनीकरण / Validation And Renewal

Registration Certificate/Renewal Date	Period of Validity/Renewal	Registration Fee Paid (In Rs.)	Items of food Manufactured handled	Signature of Registering Authority
07/03/2019	1 Year(s)	100	Please refer to annexure for details.	

Disclaimer : 1 - This Registration Certificate is only to commence or carry on the Food Business and not for any other purpose.

व्यावसाय विकास, स्वच्छता और खुदरा व्यापार पर प्रशिक्षण: - एफएसएसएआई के सहयोग से व्यवसाय विकास, स्वच्छता और खुदरा व्यापार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पटना और भागलपुर में आयोजित किए जा रहे है| स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम मे एफएसएसएआई के अधिकारी स्ट्रीट वेंडोर्स को व्यवसाय विकास, स्वच्छता और खुदरा व्यापार में प्रशिक्षित होने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। भागलपुर में 5 और पटना में 6 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। 28 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को एफएसएसएआई प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया।

राज्य के कई नगर निकायो मे TVC की बैठक हो रही है यदपि यह बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है परंतु शहर स्तरीय संघ के माध्यम से लगातार दबाव बनाया जा रहा है| इसी संदर्भ मे दिनांक 25 जून को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आहूत की गई है |

❖ तेलंगाना

राज्य सरकार ने 15 जनवरी, 2016 को योजनाओं को अधिसूचित किया है और नियमों का मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा | तेलंगाना में 30 शहर हैं, और टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) केवल हैदराबाद, कुतुबुल्लापुर, सिकंद्राबाद और शादनगर में बना है। फरवरी 2019 में टीवीसी की अंतिम बैठक हुई है |

स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण 22 शहरों कुल 72400 वेंडर्स का सर्वेक्षण हो एवं आईडी कार्ड वितरण की प्रक्रिया चल रही है | बाकी शहर मे अभी भी सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है |सभी 30 शहरों में वेंडिंग ज़ोन की पहचान की गई है, लेकिन किसी में नहीं बनाया गया है। कुतुबुल्लापुर में सड़क विक्रेताओं के साथ सहकारी मासिक बैठक होती है |

हैदराबाद: फरवरी 2019 में अंतिम टीवीसी बैठक आयोजित की गई। 22000 विक्रेताओं ने सर्वेक्षण किया और 15000 आईडी कार्ड विक्रेताओं को जारी किए। बिना किसी सुविधा के चिन्हित किए गए वेंडिंग ज़ोन को बनाया गया है।

कुतुबुल्लापुर: फरवरी 2019 में अंतिम टीवीसी की बैठक हुई। 1100 विक्रेताओं ने सर्वेक्षण किया और 900 आईडी कार्ड विक्रेताओं को जारी किए। वेंडिंग जोन को शाहपुर बाजार में बनाया गया, लेकिन उचित तरीके से नहीं।

सिकंद्राबाद: जनवरी 2019 में अंतिम टीवीसी की बैठक हुई। 800 विक्रेताओं ने सर्वेक्षण किया और 800 अस्थायी आईडी कार्ड विक्रेताओं को जारी किए। अब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया।

शादनगर: टीवीसी प्रक्रिया में है। 400 विक्रेताओं ने सर्वेक्षण किया और विक्रेताओं को 400 अस्थायी आईडी कार्ड जारी किए। अब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया।

वारंगल: 2018 में टीवीसी की बैठक आयोजित की गई। 2015 में 2000 विक्रेताओं के सर्वेक्षण किए गए और 2016-17 मे 200 विक्रेताओं को आईडी कार्ड जारी किए गए। वेंडिंग ज़ोन बनाया गया और 2016 में ही 8 वेंडिंग ज़ोनबनाए गए थे लकीन 4 को बाद मे अदालत के आदेश के अनुसार ध्वस्त कर दिया गया। । वे स्मार्ट सिटी के लिए विक्रेताओं को बेदखल करने की योजना भी बना रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है और न ही वेंडिंग प्लान तैयार किया गया है।

स्ट्रीट वेंडर्स ने कई बार नगर पालिका और संबंधित विभागों से संपर्क किया है और अधिनियम को लागू करने के लिए कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं लेकिन प्राधिकरण अनदेखी कर रहा है और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है |

❖ तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को नियम और योजनाएँ अधिसूचित की हैं। तमिलनाडु में 125 नगरपालिकाओं मे से 12 निगमों है । जिसमे अभी तक 11 निगमों में ही टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर के कारण एक निगम (त्रिची) का गठन नहीं हुआ। नगर निगमों ने वेंडिंग समिति की अभी तक बैठकों का आयोजन नहीं किया किया गया है । सभी टीवीसी बैठकों में आयोजित किए गए हैं। हमारे जानकारी के अनुसार

राजापलायम, नेल्लीकुप्पम नगर पालिकाओं और मदुरै कॉर्पोरेशन मे टीवीसी की बैठक एक बार आयोजित हुआ है । स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया गया है, पूरे तमिलनाडु में आईडी कार्ड लगभग 500 मार्केट मे वितरित किए गए हैं। लकीन ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे से बाहर रहे । इसलिए सर्वे फिर से कराया जाने की मांग की जा रही है । अब तक किसी भी वेंडिंग ज़ोन की पहचान नहीं की गई है, लकीन 225 नो वेंडिंग ज़ोन और 222 रिस्ट्रिक्टेड वेंडिंग ज़ोन की पहचान की गई है। वेंडिंग प्लान सभी 136 यूएलबी में तैयार किया गया है, लेकिन परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है।

स्मार्ट सिटी योजना के कारण बेदखली जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से त्रिची में सेवापल्ली से थुवकुडी तक के रास्ते में, ठेकेदार के द्वारा सर्विस लाने बनाने के नाम पर 19/4/19 से स्ट्रीट वेंडरों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है । इस संदर्भ मे जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं प्रतिनिधि द्वारा अरियालुर एवं **अरिअयामंगलम क्षेत्र में 25/4/19** को प्रदर्शन किया |

चेन्नई कॉर्पोरेशन में 2 टीवीसी की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। अगली बैठक चुनाव का बाद करने की बात काही गई थी । चेन्नई टी. नगर उस्मान रोड बाजार को बेदखल करने का निर्णय लिया गया। यह चेन्नई शहर के बड़े और प्रसिद्ध बाजार में से एक है। प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स बड़े आंदोलन की उम्मीद कर सकते हैं |

सभी स्ट्रीट वेंडर्स के पास पहचान पत्र है, विशेष रूप से बेदखल स्ट्रीट वेंडर्स मे से कुछ तो टीवीसी के मेंबर हैं। आईडी कार्ड में नाम, पता या फोटो में त्रुटि को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

❖ कर्नाटक

कर्नाटक राज्य सरकार ने 13 मई, 2016 को नियमों को अधिसूचित किया है और योजना बनाई, लेकिन कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सर्वेक्षण प्रक्रिया 17 सितंबर, 2017 से शुरू हो गई है। कुछ शहरों में टीवीसी का गठन किया गया है, लेकिन वे केवल मैसूर और मैंगलोर में सक्रिय हैं। अब तक, एक भी वेंडिंग ज़ोन की पहचान नहीं की गई है। मैसूर मे टाउन हाल के समक्ष प्रदर्शन भी किए गए|

बैंगलोर शहर: अब तक कोई टीवीसी का गठन नहीं हुआ 25000 विक्रेताओं का सर्वे किया और जनवरी 2018-19 में 15000 आईडी कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट बना लिए गए थे गए। अब तक कोई भी वेंडिंग ज़ोन की नहीं पहचाना गया। अगले महीने से आईडी कार्ड वितरण करने की योजना है|

मैसूर: अंतिम टीवीसी की बैठक 2018 में आयोजित की गई। 1500 विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया और 1500 आईडी कार्ड जारी किए और वेंडिंग जोन की पहचान की लेकिन अब तक कोई विकास नहीं हुआ।

बेल्लारी: अब तक कोई टीवीसी का गठन नहीं हुआ। 10000 विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है और आईडी कार्ड अभी भी चुनाव के बाद जारी करेंगे।

बीजापुर: TVC का गठन हुआ लेकिन अब तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। 2014 में 35000 विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया और 1300 आईडी कार्ड जारी किए, 2018 में और 500 आईडी कार्ड जारी किए। साथ ही 400 विक्रेताओं ने 2 महीने पहले बेदखल कर दिया। कमिश्नर और एनयूएलएम अधिकारी से शिकायत की लेकिन कोई जवाब नहीं।

गडग: दिसंबर 2018 में अंतिम टीवीसी बैठक आयोजित की गई। 2947 विक्रेताओं ने सर्वेक्षण किया और 1500 आईडी कार्ड और बटिगिरी में वेंडिंग जोन की पहचान की गई है।

हुन्सुर: 625 अस्थायी आईडी कार्ड जारी किए गए।

सभी नगरपालिका परामर्श निकाय और राजनीतिक निकाय वेंडर्स का विरोध एवं प्रताड़ित कर रहे है। वेंडर्स को सर्वेक्षण और आईडी कार्ड को क्यूआर कोड और विक्रेताओं के प्रमाण पत्र के साथ जारी करने की आवश्यकता होती है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुरोध संबन्धित पत्र सीएम और डीसीएम, यूडी मंत्री, मुख्य सचिव, कौशल सचिव, कौशल मंडल कार्यालय और नगर निगम प्राधिकरण को दिया गया है।

❖ आंध्र प्रदेश

राज्य सरकार ने क्रमशः 31 मार्च, 2017 और 15 जून, 2016 को नियमावली और योजनाएँ अधिसूचित की हैं। TVC का गठन आंध्र प्रदेश के 3 शहरों गुंटूर, श्रीकुलम और विशाखपट्टनम में किया गया है और आखिरी TVC की बैठक फरवरी 2019 में और अगली TVC जून 2019 में

आयोजित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के सभी शहरों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और कुल विक्रेताओं की संख्या 66361 है, जिनमें से 50606 विक्रेताओं को पहले ही आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं और अब चुनाव के कारण बंद हो गए हैं और अगले महीने से विजयवाड़ा, श्रीकाकुलम में फिर से शुरू होंगे , विशाखापत्तनम, गोदावार पूर्व और पश्चिम, गुंटूर, नूलोर, चित्तुर, कडप्पा, अनंतपुर, करनूर, प्रक्षाम और कृष्णा। टीवीसी के सदस्यो को पहचान पत्र वितरित किए गए है | अब तक, एक भी वेंडिंग ज़ोन की पहचान नहीं की गई है।

विशाखापट्टनम में 1 वेंडिंग ज़ोन बनाया गया, लेकिन किसी कस्टमर के के नहीं आने के कारण यह सफल नहीं हो सका ।
MEPMA ने स्ट्रीट वेंडिंग कानून का स्टेट लेवेल पर समीक्षा बैठक की है|
गुंटूर नगरपालिका मे टीवीसी की बैठक हुई जिसमे आईडी कार्ड जारी करने पर चर्चा हुई |
विजयनगरम मे 160 स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग आईडी कार्ड जारी किए गए है|

❖ केरल

राज्य सरकार ने नियम और योजनाएँ बनाई हैं। कुल 93 में से सभी 76 ULBs में TVC का गठन किया गया है | सर्वेक्षण सभी 93 यूएलबी मे किया गया है एवं 19751 विक्रेताओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है, जिसमें से 5 ULBs में 1357 विक्रेताओं यानी मलप्पुरम, शोर्नूर, चालकुडी, त्रिशूर, और चावक्कड को आईडी कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक, एक भी वेंडिंग ज़ोन की पहचान नहीं की गई है।

केरल सरकार ने 2018 मार्च पंचायत स्तर के स्ट्रीट वेंडर सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की लेकिन आज तक शुरू नहीं हुई।

पालघाट: नगर पालिका द्वारा मार्च 2018 के मध्य में पालघाट में जारी किए गए 652 पहचान पत्र। टीवीसी सदस्यों को कार्ड भी वितरित किए गए।अंतिम टीवीसी बैठक 2018 में आयोजित की गई। नो वेंडिंग जोन की पहचान की गई।

पलक्कड़: नगर पालिका में 52 वार्ड हैं, नगर पालिका द्वारा 675 वेंडर्स का सर्वेक्षण किया गया है जिसमे 550 वेंडर्स को आईडी दिये गए है | नवंबर 2018 मे टीवीसी का गठन किया गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरा सर्वेक्षण किया जाएगा।

कोचीन नगर निगम: 74 वार्डों का सर्वेक्षण किया गया। अभी तक टीवीसी का गठन नहीं हुआ है। स्ट्रीट वेंडर के सर्वेक्षण में 1987 विक्रेताओं का चयन किया गया। 137 विक्रेताओं को आईडी कार्ड जारी किए गए।

त्रिचूर निगम: सड़क विक्रेता का सर्वेक्षण प्रगति पर है।

कन्नूर जिला: इरिट्टी नगरपालिका ने उच्च न्यायालय के आदेश से विक्रेताओं को हटा दिया गया है।

केरल के कन्नूर में नेशनल फुट पाथ अंडरवंडी पेटीकाडा थोझिलाली यूनियन की राज्य कार्यसमिति की बैठक हुई | केरल के कन्नूर जिले में हुई बैठक मीटिंग में स्ट्रीट वेंडर्स के प्रति केरल सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है और आईडी कार्ड जारी नहीं हो रहा है। विक्रेताओं को लाइसेंस देने की कार्रवाई नहीं। हमने 3 महीने के भीतर कन्नूर में अपनी राज्य सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

❖ राजस्थान:

राजस्थान के रूल्स, स्कीम्स एवं TVc बनी हुई है, लेकिन TVc की कहीं भी नियमित मीटिंग नहीं होती है कोटा में कुल 5443 लोगों का सर्वे हो चूका है, पहचान पत्र किसी को नहीं मिला है |

माउंट अबू मे भी 200 से जयादा लोगों का सर्वे किया गया है, माउंट अबू नाछी लेक को नगर पालिका एवं ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा सौंदर्यीकरण विकास का कार्य किया जा रहा है जैसे लाइट, शौचालय आदि का निर्माण किया गया है|

विदया नगर:- विदया नगर में कोर्ट के आदेश के बाद 40 - 50 लोगों को दुकान बनाकर दिया गया है |

पाली मे अभी तक तीन सो वेंडर्स को परिचय पत्र दिये गये लगभग सात सो वेंडर का सर्वे हुआ था |

जयपुर में TVc की 3 मीटिंग हुई है, जिसमे 1 मीटिंग को वेंडर प्रतिनिधि के द्वारा बहिस्कार किया गया है| क्योकि मीटिंग की मिनट्स में केवल निगम अपने ही बात को ही रखती थी | वेंडर्स की बात पर कोई जगह नहीं होती थी| सर्वे के लिए चेनई की एक कंपनी को दिया गया है अभी केवल 7321 लोगों की फॉर्म भरा गया है|

बीकानेर मे वेंडर्स को आईडी कार्ड: 12 जून को बीकानेर टाउन वेंडर कमेटी की मीटिंग हुई | बीकानेर के 2695 रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया |अधिकारीगण ने बहुत जल्दी सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया |इस दौरान शहर मे कार्य कर रही एजन्सि के द्वारा 4 ज़ोन मे कुल 21 वेंडिंग जोने का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं सभी वेंडर्स को शीघ्र ही पहचान पत्र व वेंडिंग सर्टिफिकेट देने पर भी सहमति बनी |

जोधपुर: शास्त्रीनगर सर्कल मे फूड वेंडर्स ने यह निर्णय लिया गया की एक्ट 2014 के बाद भी स्ट्रीट वेंडर्स को आये दिन नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स अब जोधपुर हाईकोर्ट मे नगरनिगम व पुलिस प्रशासन के खिलाफ याचीका लगायेगे | 6234 वेंडर्स का सर्वे हुआ है 300 लोगों को पाली में पहचान पत्र मिला है| राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश पत्र जारी किया गया है जिसमे नगर निकायों द्वारा पथ विक्रेताओं को बेदखल एवं स्थानांतरित करने के लिए 2014 के पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं व्यवपार अधिनियम 2014 कानून के हिसाब से पालन करने को कहा गया है|

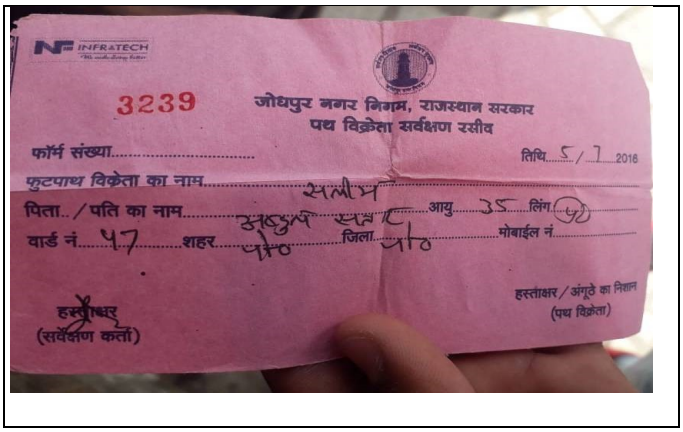

18 मार्च को नई सडक पर स्ट्रीट वेंडर्स की आम सभा का आयोजन किया गया जिसमे सभी स्ट्रीट वेंडर्स को एक्ट 2014 के तहत यूनियन संयोजक व नासवी कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश देवडा के नेतृत्व मे यातायात उप अधीक्षक श्रीमती निर्मला विशनोई एवम यातायात निरीक्षक श्रीमान रिछपाल शेखावत ने नई सडक स्ट्रीट वेंडर्स को एक्ट के अनुसार व्यवस्थित रूप से व्यापार करने ओर अपने व्यवसायिक स्थल को साफ सुथरा रखने के बारे मे जानकारी साझा की | आम सभा मे यूनियन का चुनाव भी सम्पन्न हुआ जिसमे संगठन के श्री ओम प्रकाश देवडा को सर्व सम्मति से पुनः अध्यक्ष कर चयनित किया गया संगठन के चुनाव एडवोकेट श्रीमान अ. कययूम, शंकर लाल माखेचा ओर राजेन्द्र वेषणव की देखरेख मे स्ट्रीट वेंडर्स की उपस्थिति मे हुआ।

टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यो का प्रशिक्षण: 12 अक्तूबर 2018 को जयपुर मे टाउन वेंडिंग समिति के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया| प्रशिक्षण मे 7-8 नगर निकायो के लगभग 30 सदस्यो ने भाग लिया| प्रशिक्षण के दौरान सदस्यो ने बताया की जयपुर में टाउन वेंडिंग कमिटी की सुनवाई नहीं होती | नगर निगम की हठधर्मिता के कारण वेंडर्स अपनी बात नहीं रख पते | इस बात पर स्थानियों प्रतिनिधियों के बीच बहस छिड़ गई एवं वेंडर्स प्रतिनिधि आपस मे ही एक दूसरे पर दोष रोपण करने लगे|

झुंझुनू - नगर परिषद द्वारा राजस्थान शहरी पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विनियमन) नियम 2016 के तहत नगर परिषद क्षेत्र के थड़ी, ठेले एवं फुटकर विक्रेताओं को अपनी पहचान देने व शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में नगर परिषद आयुक्त विनयपाल ने बुधवार को फुटकर विक्रेताआ को योजना के तहत पहचान कार्ड वितरित कर वैण्डिंग जोन में स्थापित करने का कार्य मण्डावा मोड़ से प्रारम्भ किया। आयुक्त ने बताया कि शहर को सुन्दर एवं साफ सुथरा बनाने की दृष्टि से थड़ी, ठेले फुटकर विक्रेताओं को पहचान कार्ड दिया जाकर, उन्हें एक निश्चित जगह प्रदान किये जाने का कार्य मण्डावा मोड़ से एनयूएलएम टीम व राजीव जानू मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगर परिषद टीम द्वारा प्रारम्भ किया गया। शहर के समस्त पथ विक्रेताओं को नॉन-वैंडिंग जोन से वैंडिंग जोन में स्थायी जगह पर स्थापित किया जाना है।

❖ पंजाब:

रेहड़ी फड़ी फेडरेशन के प्रधान टाइगर सिंह अपने टीम के साथ नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात कर स्ट्रीट वेंडर योजना लागू करवाने की मांग को रखा ⇒ जागरण

सिद्धू से मांग, जल्द बनाए जाएं वेंडर जोन

जासं, लुधियाना : रेहड़ी फड़ी फेडरेशन के प्रधान टाइगर सिंह की अगुवाई में शिष्टमंडल स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से मिला और उन्हें मांगपत्र सौंपा। टाइगर सिंह ने बताया कि प्रदेश में वेंडिंग जोन बनना है। यह योजना वर्ष 2014 से चल रही है और अभी तक किसी भी शहर में वर्क आरंभ नहीं होने से रेहड़ी-फड़ी वाले चिंतित है। उन्होंने सिद्धू को बताया कि लुधियाना में वेंडिंग जोन का सर्वे भी हो चुका है लेकिन दुकानें बनाने के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। टाइगर सिंह ने कहा कि फेडरेशन टीम ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वेंडर जल्द बनाने के निर्देश दिए जाएं। शिष्टमंडल में सतपाल सिंह, करणजीत सिंह संधू, अश्वनी कुमार महाजन शामिल रहे।

पंजाब में रूल्स एवं स्कीम बना हुआ है तथा TVC का गठन हो चूका है | कुल 21622 लोगो का सर्वे किया गया है जिसमे 900 वेंडर्स का सर्टिफिकेट तैयार है लेकिन अभी किसी को दिया नहीं गया है| पंजाब के विभिन्न शहरो मे वेंडिंग ज़ोन बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है एवं वेंडिंग कार्ड देने की भी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है परंतु कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभी बहुत कुछ होना बाकी है| पंजाब मे मुख्यमंत्री द्वारा इस कानून के अनुपालन की दिशा मे समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये गए थे परंतु नतीजा सिफर है | यदपि लुधियाना मे दुकानदारो से 1500, 2000 ,2200 रु प्रति वेंडर्स प्रति माह नगर निगम को क्रिटेरिया के हिसाब से वेंडर्स नगर निगम को जमा कर रहे है |

SMS

Know the true value of time; snatch, seize and enjoy every moment of it. No idleness, no delay, no procrastination; never put off till tomorrow what you can do today.

लुधियाना केसरी

विचार

SATURDAY, 10 NOV 2018. LUDHIANA KESARI

पहला कोलम

तबाजारी टीम के साथ हुए विवाद का मामला

रेहड़ी-फड़ी वालों ने घेरा निगम ऑफिस

लुधियाना मे हाल मे ही हुए टीवीसी के बैठक मे ज़ोन सी मे 9 क्षेत्र मे वेंडिंग ज़ोन बनाने पर सहमति बनी एवं सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गए है | इससे पूर्व करीब 40 क्षेत्रो मे वेंडिंग ज़ोन बनाने पर चर्च हुई थी|

नगर विकास मंत्री **नवजोत सिंह सिद्धू को ज्ञापन** देकर कानून लागू करने की मांग की गई|

❖ पश्चिम बंगाल:

अनेक जद्दो जहद के बाद पश्चिम बंगाल मे स्ट्रीट वेंडिंग नियमावली 2018 का गठन कर दिया गया है | परंतु अभी तक कही पर भी क्रियान्वयन होने की सूचना नहीं है| नासवी के सदस्य संगठन ने सरकार को स्थिति से अवगत करवाया है| यह दुखद एवं विचारणीय है की इतने संगठनो के वाओजूद भी सूचना प्राप्त नहीं होती|

JAI HIND CALCUTTA HAWKERS' UNION

Regd. No. : 18300 ★ Affiliated with INTUC

H.O. & Correspondence : 7B, Rani Rashmoni Road, Kolkata-700013, Ph : 3092 1195
Camp. Office : 'Maruti Building', 12, Loudon Street, Kolkata - 700 017, Ph : 2280 1805

HAWKERS SITUATION AT KOLKATA

Due to hawkers shade, there caused a huge fire hazards in Gariahat, Kolkata wherein it damaged buildings and also about 85 vendor kiosks. The Kolkata Municipal Corporation (KMC) have arbitrarily constructed tin kiosks of same size and is forcing the hawkers/vendors to install it replacing their old stall structures irrespective of being bigger or smaller. Moreover, KMC without discussion and coming out with a viable replacement have directed the hawkers not to use plastic shades which protects them from sun and rain.

That in a similar pattern, the KMC are forcing hawkers of Sealdah, Hatibagan and Burrabazar to make small hawking structure and remove all plastic shades arbitrarily.

That the KMC have not formed Town Vending Committee in accordance to the guidelines of the act and are only discussing all issues with TMC led unions debarring representatives from all other unions like Jai Hind Calcutta Hawkers Union and others unions affiliated with RSP, CITU, AITUC, AICCTU, HMS etc.

That we had collectively taken up the matter before the Hon'ble High Court, Kolkata for the formation of Town Vending Committee to which the Hon'ble Court have directed KMC to act as prayed for. But this effort too have gone in vein and we have decided to approach again before the High Court so that we are included and/or KMC constitute Town Vending Committee.

That Jai Hind Calcutta Hawkers Union is acting for years together effectively to the needs of hawkers and we are also planning to get a Railway Hawkers Union registered very soon. A Committee to that effect have already been constituted.

CR Pandey

(Chandra Rekha Pandey)
President

❖ गुजरात:

गुजरात में रूल्स एवं स्कीम बनी हुई है और ज़्यादातर नगर निकायो मे TVC का गठन किया गया है| सूरत में 2014 में 35114 लोगों का सर्वे हुआ 2016 में 18140 लोगों का सर्वे हुआ अभी | अहमदापाक कंपनी ने 28340 लोगों का सर्वे किया जो सही नहीं है| इसलिए वेंडर्स के द्वारा विरोध किया गया है 14000 लोगों का हौकिंग का पहचान पत्र दिया गया है| जिसमे 108 कुवेर नगर कपडा वेंडर्स कोर्ट का रहे है क्योकि नगर निगम हौकिंग पहचान पत्र देकर वेंडर्स को ठग रही है| नगर निगम ने एक जीरो दबंग आदेश जारी किया जिसके लोरी वाले (रेहड़ी वाले) को पकड़ते और 2000 का फाइन वसूलते है और 500 का रसीद देते है और साथ में एक शपथ पत्र लेते है की हम वह दोबारा नहीं लगाएंगे | जीरो दबंग आदेश के कॉपी के लिए RTI फाइल किया गया है| भावनगर में TVC की प्रॉपर मीटिंग नहीं होती है 600 लोगों को 2006 में हाई कोर्ट से स्टे मिला|| 200 वेंडर्स को 2016 में हाई कोर्ट से स्टे मिला| अभी सर्वे नहीं हुआ है |

❖ उत्तराखंड

बुधवार को हरिद्वार के नगर निगम सभागार में फेरी समिति की बैठक लेते नगर आयुक्त आलोक पांडे ● जागरण

11 मार्च से एक बार फिर होगा वेंडरों का पंजीकरण

हरिद्वार: नगर निगम के सभागार में बुधवार को टाउन वेंडिंग प्लानिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि वेडिंग जोन में वेंडरों को बसाने के लिए फिर से पंजीकरण के लिए 11 से 30 मार्च तक अवसर मिलेगा। वहीं ज्वालापुर में सब्जी बेचने के लिए वेडिंग जोन का निर्धारण कर शुरू कराने पर सहमति बनी।

नगर आयुक्त आलोक पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेहड़ी पटरी हाथ ठेली लघु व्यवसायियों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा आदि भी मौजूद रहे। इसमें चर्चा में सामने आया कि पिछली बार हुई सर्वे में ढाई हज़ार के करीब स्ट्रीट वेंडर हैं। मगर इसमें से हकीकत में अब कितने वास्तविक हैं इनके पंजीकरण कराने के लिए फिर से तारीख तय करने की बात हुई। जिसमें तय किया गया कि 11 से 30 मार्च तक पंजीकरण चलेगा। इसमें दस रूपये के निर्धारित प्रोफार्मा पर 100 रुपये शुल्क जमा कर स्ट्रीट वेंडर अपना पंजीकरण कराएंगे।

साथ ही यह भी चर्चा हुआ कि नये क्षेत्रों में भी वेडिंग जोन बनाने के लिए कदम बढ़े। नगर आयुक्त आलोक पांडेय ने बताया बैठक में तय हुए निर्णयों के अनुसार वेडरों को फिर से पंजीकरण कराना है। इसके बाद आखिरी तस्वीर साफ होने के बाद वेडिंग जोन बनाकर उसका लाभ दिलाया जाएगा। बैठक में सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार, वरिष्ठ 1/1 ीक्षक सुनीता सक्सेना सहित अन्य उपस्थित रहे। (जासं)

उत्तरांचल मे रूल्स स्कीम बने हुए है एवं TVc का गठन हुआ है | हरिद्वार मे कुल 2547 लोगों का सर्वे हुआ है, पहचान पत्र के लिए 110 रु प्रति ठेला नगर निगम को पंजीयन शुल्क दिया गया है| नगर निगम स्थानीय वेंडर्स से 20 रु प्रति दिन लेती है और बाहर के वेंडर्स से प्रति दिन प्रति वेंडर्स 200 रु लेती है| महीने का 5000 नगर निगम लेती है | देहरादून TVc की नियमित मीटिंग नहीं होती| कुल 2000 वेंडर्स का सर्वे किया गया है| 200 वेंडर्स को वेंडिंग जोन घंटा घर में पहचान पत्र मिला है| 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किया गया है, जिसमे 8 - 10 वेंडिंग जोन में दुकानदार जाते है | नासवी से सदस्य सरी संजय चोपड़ा ने हाल मे ही महापौर श्री सुनील गामा से मिलकर लघु व्यापारियों को व्यवस्थित करने का

अनुरोध किया है|

धरमपुर में भी TVc का गठन हुआ है पर 2 साल से TVc की कोई मीटिंग नहीं हुई है| 2900 वेंडर्स का सर्वे किया गया है, सभी को वेंडिंग पहचान पत्र दिया गया है|

मसूरी मे नासवी के पहल पर टीवीसी का गठन

दिनांक 26/04/2019 मसूरी क्षेत्रानान्तर्गत नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में माल रोड से अतिक्रमण के नाम पर सभी रेहड़ी पटरी व्यसाइयो को नगरपालिका तथा प्रशासन के द्वारा उनके विक्रय स्थान से हटा दिया गया| शोशल मीडिया पर वाइरल हुए वीडियो के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ | मसूरी में स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए नासवी ने वस्तुस्थिति का जाएजा लेकर पहल की | वहाँ विभिन्न मार्किट में स्थानीय लीडर्स के साथ जाकर भी मुलाकात की, यहाँ पर मसूरी क्षेत्रानान्तर्गत नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में 13 वार्ड है जिसमे मुख्यतः माल रोड, वार्ड नंबर 8 में वेंडर्स की जनसँख्या सबसे अधिक है, तथा यही पर ज्यादा वेंडर्स को परेशांन किया जाता है, यहाँ कुल वेंडर्स से संख्या 400 से 500 है|

नासवी द्वारा अधिशासी अधिकारी (EO) नगरपालिका परिषद् , SDM को पत्र लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से मुलाक़ात कर टीवीसी के गठन एवं स्ट्रीट वेंडिंग कानून 2014 एवं राज्य नियमावली का हवाला दिया गया | यदपि टीवीसी का गठन पूर्व मे हुआ था मगर ये शिर्फ कागजी खनपूर्ति थी | अधिशासी अधिकारी (EO) नासवी के दलील मानते हुए TVC का गठन हेत पत्र नियमवाली 2016 के धारा 12 (2) के अनुसार नासवी सहित सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को भेजा गया एवं दिनांक 17-06-2019 को इसकी गठन के बैठक का आयोजन किया गया ।

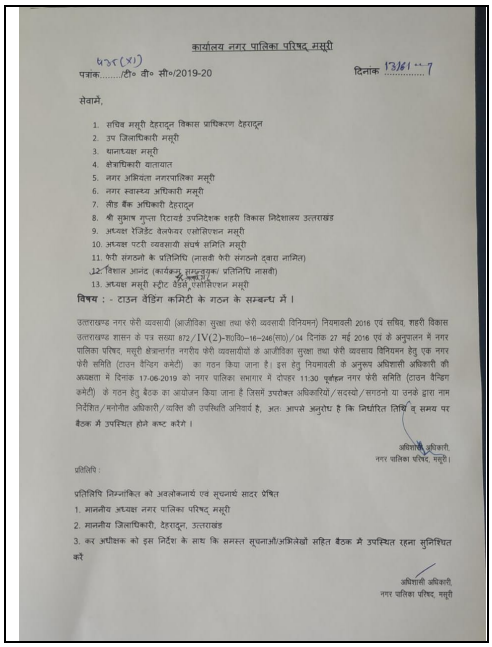

कार्यालय नगर पालिका परिषद् मसूरी

पत्रांक 435(XI)/टी० वी० सी०/2019-20 दिनांक 13/6/...7

सेवामें,

1. सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून
2. उप जिलाधिकारी मसूरी
3. थानाध्यक्ष मसूरी
4. क्षेत्राधिकारी यातायात
5. नगर अभियंता नगरपालिका मसूरी
6. नगर स्वास्थ्य अधिकारी मसूरी
7. लीड बैंक अधिकारी देहरादून
8. श्री सुभाष गुप्ता रिटायर्ड उपनिदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड
9. अध्यक्ष रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी
10. अध्यक्ष पटरी व्यवसायी संघर्ष समिति मसूरी
11. फेरी संगठनो के प्रतिनिधि (नासवी फेरी संगठनो द्वारा नामित)
12. विशाल आनंद (कार्यकर्ता, समन्वयक/ प्रतिनिधि नासवी)
13. अध्यक्ष मसूरी स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन मसूरी

विषय : - टाउन वेंडिंग कमिटी के गठन के सम्बन्ध में ।

उत्तराखण्ड नगर फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसायी विनियमन) नियमावली 2016 एवं सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 872/IV(2)-शाविo-16-246(सा0)/04 दिनांक 27 मई 2016 एवं के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, मसूरी क्षेत्रान्तर्गत नगरीय फेरी व्यवसायीयों के आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन हेतु एक नगर फेरी समिति (टाउन वैन्डिंग कमेटी) का गठन किया जाना है। इस हेतु नियमावली के अनुरूप अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 17-06-2019 को नगर पालिका सभागार में दोपहर 11:30 पूर्वाह्न नगर फेरी समिति (टाउन वैन्डिंग कमेटी) के गठन हेतु बैठक का आयोजन किया जाना है जिसमें उपरोक्त अधिकारियों/सदस्यों/संगठनों या उनके द्वारा नाम निर्देशित/मनोनीत अधिकारी/व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है, अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित तिथि व समय पर बैठक में उपस्थित होने कष्ट करेंगे ।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

प्रतिलिपि :

प्रतिलिपि निम्नांकित को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित

1. माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् मसूरी
2. माननीय जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड
3. कर अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि समस्त सूचनाओं/अभिलेखों सहित बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अधिशासी अधिकारी ने नासवी से आग्रह किया की नगरपालिका परिषद् को TVC के गठन तथा रेहड़ी पटरी व्यवसाइयों की उतराखंड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमवाली 2016 को लागु करने तथा सर्वे करने में मदद करें ।
(*विस्तृत रिपोर्ट अगल से संलग्न है*)

❖ छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में नासवी के 576 वेंडर्स सदस्य है | रूल्स और स्कीम है एवं TVC बना हुआ है | रायपुर में 20 वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित किया गया है| 4 - 5 वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है और 300 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है| फूटकर व्यापारी कल्याण संघ का विस्तार बिलासपुर , विलाई , और रायगढ़ में किया गया है|

❖ जम्मू - कश्मीर

कश्मीर में नासवी के 68 वेंडर्स सदस्य है जम्मू - कश्मीर के श्री नगर में रूल्स , स्कीम और TVc नहीं है| फूटपाथ विक्रेता के विषय पर नगर निगम से 2 - 3 मीटिंग हुई है | यहाँ नासवी के द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए मोबेलाईजेसन कार्य किया गया था परंतु कुछ तकनीकी कारणो से इसे अंजाम नहीं दिया जा सका |

नगर आयुक्त, श्रीनगर के साथ बैठक - श्रीनगर के नगर आयुक्त के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमने सड़क विक्रेताओं के मुद्दों और विक्रेताओं की आजीविका में सुधार के लिए NASVI की पहुंच के बारे में बात की थी। NASVI ने विक्रेताओं को प्रशिक्षण देने के दृष्टिकोण को साझा किया । यह नगर निगम आयुक्त के साथ सबसे अच्छे अनुभवों में से एक था; हमें उम्मीद है कि श्रीनगर में हम कुछ ऐतिहासिक कर पाएंगे। इस स्तर पर किसी भी प्रगति की कल्पना करना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह बैठक एक सकारात्मक संकेत है कि भविष्य में सड़क विक्रेताओं से संबंधित मामलों में अधिक विकास होगा।

जम्मू और कश्मीर में खाद्य विक्रेताओं के प्रशिक्षण का सफल समापन

लगभग 500 स्ट्रीट खाद्य विक्रेतावों को नासवी एवं नेसले के द्वारा स्वकच्छता पर प्रशिक्षण दिया गया| ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, J & K (DFCO) ने भी आगे आकर प्रशिक्षण शुरू करने में सहयोग दिखाया है। टीम NASVI और नेस्ले द्वारा की गई कार्यक्रम पूर्व की तैयारी सराहनीय थी। जम्मू और कश्मीर के विक्रेता उनके लिए इस तरह के प्रशिक्षण के लिए खुश थे, क्योंकि उन्हें अपनेपन का अहसास था |

खाद्य विक्रेताओं का प्रशिक्षण विवरण जम्मू और कश्मीर			
S.N	**Date**	**Venue**	**Total Participated**
1	12-10-18	Rubi Hotel	70
2	14-10-18	Rubi Hotel	40
3	16-10-18	Broad View	35
4	21-10-18	Shree Nagar	30
5	22-10-18	Shree Nagar	40
6	29-10-18	Makki Point	65
7	26-12-18	SidkiChowk	50
8	27-12-18	SidkiChowk	50
9	29-12-18	Katra	60
10	02-01-19	Chhani Rama	60
Total			500

शपथ लेते हुए स्ट्रीट फूड वेंडर्स

❖ नागालैंड

2017 के विश्लेषण अध्ययन से पता चला है कि नागालैंड राज्य में स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के कार्यान्वयन पर कोई काम नहीं किया गया है जिसका अर्थ है कि कोई नियम और योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। उन्हें टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करना बाकी है। इसलिए, 2019 तक आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

❖ असम

असम में मुख्य अधिनियम के तहत नियमावली बनाए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2016 असम के राज्यपाल के आदेशों के तहत बनाए और पारित किए गए हैं। नियमों ने सड़क विक्रेताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसमें जोर दिया गया कि केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर गुवाहाटी नगर निगम के लिए राज्य सरकार द्वारा और अन्य नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकायों के लिए संबंधित नगर पालिकाओं या टाउन समितियों द्वारा टाउन वेंडिंग समितियों का गठन किया जाएगा | 2019 तक असम मे 25 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिन्हें वेंडिंग अधिनियम के तहत कवर किया गया है।लकीन असम में किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में योजनाओं को तैयार नहीं किया गया है।

प्रत्येक ULB में TVC का गठन किया गया है, लेकिन यह जल्दबाजी में बनाया गया है | कोकराझार, धेमाजी, दीफू, गोलाघाट, हैलाकांडी जैसे अधिकांश यूएलबी में पहचान किए गए पर वेंडिंग जोन की सूचना पर कोई जानकारी नहीं है। टाउन वेंडिंग कमेटियां सुस्त पड़ गई हैं। 25 में से केवल 11 ULBs में ही कुछ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी की गई है। किसी भी ULB में वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं और न ही कोई वेंडिंग प्लान ही बना है ।

❖ मिजोरम

मिजोरम मे 28 नवंबर 2017 को, मिजोरम के राज्यपाल ने मिजोरम के स्ट्रीट वेंडरों (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग की विनियमन) योजनाओं किया, 2017 एवं 2 नवंबर 2017 को, मिजोरम स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) नियम, 2017 पारित किया। 2019, जून तक सभी 8 यूएलबी में टीवीसी का गठन किया गया है। निवारण समिति और अपीलीय प्राधिकारी के गठन पर काम प्रक्रिया में है। टीवीसी की नियमित बैठकें हो रही हैं। मिजोरम में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जो नियम और योजनाओं के अनुसार मिजोरम सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं:

1) आइजोल शहरी क्षेत्रों के लिए वेंडिंग योजना और बाजार विकास योजना का विकास

2) मिजोरम में स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए वेंडिंग कार्ट का वितरण

3) नागरिक चार्टर की तैयारी को वाजिब भाषा में जारी किया जाए

4) मिजोरम में सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सर्वे किया जाना है

समय आधारित वेंडिंग ज़ोन का प्रत्यक्ष उढाहरण - पारित किए गए ज़ोन, लोकल वाइज

1. **KAHRAWT VENG, CHAMPHAI**:

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks
1	Dawrkaikawn	5:00-10:00 AM & 2:00-5:00 PM	Temporary Vending Zone
2	Near PHE Tanky	5:00-10:00 AM & 2:00-5:00 PM	Temporary Vending Zone
3	Near Lunghnema Traffic Point	5:00-10:00 AM & 2:00-5:00 PM	Temporary Vending Zone

2. ELECTRIC VENG, CHAMPHAI

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks
1	C.Denga Gate to 7th Day Church Crossroad	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
2	Modern Meat Shop ground floor verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
3	Modern Meat Shop 1st floor Verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
4	Thavunga Verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
5	Lalkhawchhana Verandah	6:00 AM- 6:00 PM	Stationary Vending Zone
6	Near SBI Main Gate	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
7	Mawmi Variety Store Verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone

3. VENGLAI, CHAMPHAI

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks
1	Near TC Restaurant Crossroad	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
2	Near Venglai VC Lungphun	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
3	Peter Munga's Corridor	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
4	Left porch of Mizo Drug Store	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
5	TVS Store verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
6	V.Tlanglawma cyber world verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
7	Near JK Store	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending

4. VENGTHLANG, CHAMPHAI

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks
1	Sangchia Building Varandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
2	Near PS-II Gate (East)	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
3	PuThanrawia (L) Corridor	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
4	Apex Bank Corridor	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone

5. **BETHELVENG, CHAMPHAI**

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks
1	Bethel Kawn near Khuangchhuma's Building	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
2	Below Forest Office	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
3	R.Lalzinga Verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
4	Ronguri Verandah	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone
5	Lianthuama Building Verandah	Till 7:00 AM	Temporary Vending Zone

6. VENGTHAR, CHAMPHAI

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks

1	ThingsulthliahKawn near YMA Office	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone

7. KANAN VENG, CHAMPHAI

Sl.No	Location	Vending Time	Remarks
1	Kanan road-side market	6:00 AM – 6:00 PM	Stationary Vending Zone

❖ मेघालय -

शिलांग में 2 टीवीसी। एक नगरपालिका और दूसरा गैर नगरपालिका। अन्य टीवीसी प्रक्रिया में हैं। (प्रक्रिया में संकलन)।

❖ त्रिपुरा

त्रिपुरा में, 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार, नियम और योजनाएँ बनाई गई हैं।

❖ ओड़ीशा

20 जनवरी को भुवनेश्वर मे नेशनल स्ट्रीट वेंडर्स दिवस का आयोजन स्थानीय संगठन द्वारा किया गया|

सुरक्षित खाद्य सेवा @ स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट की सेवा करें

नासवी ने नेस्ले इंडिया के साथ मिलकर, ओड़ीशा के कटक, भूबनेश्वर एवं पूरी मे स्ट्रीट फूड वेंडर्स का प्रशिक्षण किया | तीन चरणो मे कुल 1001 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण दिया गया एवं बाद मे उन्हे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिये गया | भूबनेश्वर मे 510, पूरी मे 250 एवं कटक मे 241 स्ट्रीट फूड वेंडर्स शामिल हुए |

प्रशिक्षण निम्न मुद्दो पर आधारित है-

- *स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है - स्वच्छता का उल्लेख करने में हाइजीन के प्रकार, व्यक्तियों की भूमिका*
- *हाथ धोने और स्वच्छता*
- *डिस्पोजेबल हाथ के दस्ताने का उपयोग*
- *गाड़ी की हाइजीन और खाना पकाने की जगह*
- *अपशिष्ट डिस्पोजेबल - ठोस और तरल*
- *खाद्य पदार्थों के तापमान को समझने की बुनियादी समझ - कोल्ड स्टोरेज, वार्म स्टोरेज, फ़ोरोज़ेन स्टोरेज*
- *परिवर्तन, खाद्य पदार्थों का संदूषण*
- *ग्राहक सेवा*
- *खाद्य लाइसेंस की प्रक्रिया*

कुछ विक्रेताओं ने कहा कि पहले बहुत कम लोग उनकी ठेले पर आते थे, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जब उन्होंने एप्रन पहना टोपी और दस्ताने पहने तो लोग उनकी गाड़ी में आने लगे। विक्रेताओं ने अपने कार्यस्थल पर पोशाक पहनने से उनकी दैनिक आय में वृद्धि हुई और जो प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए, उन्होंने हमें कई बार पूछा कि अगला प्रशिक्षण कहां आयोजित किया जाएगा। लेकिन हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। इसलिए विक्रेताओं ने खुद एप्रन, कैप और दस्ताने खरीदे और उन्हें अपने कार्यस्थल पर इस्तेमाल किया।

❖ *महाराष्ट्र*

महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक अतिक्रमण अभियान में स्ट्रीट वेंडरों को उनके ठेले और सामान को जबरन हटा कर एवं चालान कट कर परेशान किया गया था | NASVI प्रतिनिधि द्वारा 2014 स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से अभियान को बाधित किया गया था, जिसके अनुसार उन्हें वेंडरों को बेदखल करना कानूनी नहीं है। अकोला नगर पालिका के प्रमुख श्री मिश्रा के संज्ञान में कानून के प्रावधान को लाया गया, जिसके कारण स्ट्रीट वेंडरों को उन स्थानों से अपनी वेंडिंग संचालित करने की अनुमति दी गई |

पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉकर मार्केट पेट्री प्रोफेशनल पंचायत महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर सचिव बालासाहेब मोरे, यहाँ लगभग 87 विक्रेताओं को स्थायी रूप से यूनिकॉन में बहाल किया गया है और उसी का नाम पठारी प्रोफेशनल पंचायत, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकरमोलादिना हॉल, पुणे मार्केट है।

पुणे मे व्यस्थित दुकानदार

अंधेरी मे परेशान दुकानदार

राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल

बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर खाद्य पदार्थ बेचते हैं, नासवी ने एक स्ट्रीट फूड प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें खाद्य विक्रेताओं के क्षमता निर्माण और प्रदर्शन और स्ट्रीट फूड के आकर्षण के बारे में समाज को संवेदनशील बनाया है। गत वर्ष FSSAI के नेतृत्व मे कई विभागो के संयोजन से NASVI ने फूड फेस्टिवल का आयोजन किया| इस आयोजन के बाद शहरी विकास मंत्रालय ने कुछ नीतिगत निर्णय लिए एवं पूरे भारत मे शहरी समृद्धि उत्सव के आयोजन के द्वारा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया |

भागीदारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का 10 वां संस्करण बहुत सफल रहा। इसका मतलब यह है कि स्ट्रीट फूड पर रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं सवाल उठाने वालों पर कि स्ट्रीट फूड अस्वास्थ्यकर है और अनहेल्दी हमारे, को प्रयासों ने मित्थ को तोड़ा है ।

पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत में मैत्रीपूर्ण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अपने स्टाल के साथ समारोह स्थल पर मौजूद थे। भारत में यात्रा और जिम्मेदार पर्यटन के बारे में प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए लोगों ने इस पहल में दिलचस्पी दिखाई और स्टाल के पास रुक कर देखा सुना । पर्यटन के नक्शे और ब्रोशर के वितरण के लिए प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी, जिसने हमारे खूबसूरत देश की विविधता को बढ़ावा दिया। 25 राज्यों के 500 से अधिक व्यंजनों को लोगों के लिए परोसा गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मखन मलायी, लिट्टी चोखा, दाबेली, चिकन 65, पथर गोश्त, इल्ली पाथिरी, किल्ली कुडु, मुता मिरखथु, गोंगुरा पाचरी, इमली चावल, नारिकुल लड्डू, तिल पिठा, मोआ, कच गोला, जैसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट भोजन। टमाटर चाट, इमरती रबड़ी, बाजड़े की रोटी, दही के शोले, इनसाइलेटर, सिपु बदी, मंडी कचौरी, चीनी डोसा, लिट्टी-मीट, चिकन हलीम, मक्के की रोटी, चूर चना नान, चिकन चेंजजी, दौलत की चाट, बिरयानी, इत्यादि । ,

शहरी समृद्धि उत्सव- दिल्ली

नई दिल्ली - 7 फरवरी 2019 - शहरी अर्थव्यवस्था और शहर की समृद्धि में स्ट्रीट वेंडर्स के महत्व को पहचानने और पता लगाने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने स्ट्रीट फूड के 40 स्टाल लगाने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया को आमंत्रित किया है जहां शहरी समृद्धि उत्सव और एक विशाल भोज्य थाली बनाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनोंका स्वाद ले सकते हैं। सभी अलग-अलग विक्रेताओं के साथ पूरे भारत में सभी लोगों के लिए व्यंजनों का प्रयास करने का पर्याप्त अवसर है।

नासवी का मानना है कि कई देश स्ट्रीट फूड को संरक्षित करते हैं और बढ़ावा देते हैं क्योंकि स्ट्रीट फूड एंटरप्राइज स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन में काफी योगदान देता है। पारंपरिक स्ट्रीट फूड की अवधारणा ने विकसित देशों में नए आयाम हासिल किए हैं, जिसमें फूड स्ट्रीट / फूड सेंटर नए पर्यटक आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं।

साक्ष्य यह भी बताते हैं कि होटल और रेस्तरां में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में अच्छी सामग्री और पानी के सुरक्षित संचालन से तैयार स्ट्रीट फूड में अधिक पोषण मूल्य होते हैं। उत्सव मे 100 से अधिक स्ट्रीट फूड वेंडर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी क्षमता बनाने की कसम खाई।

शहरी समृद्धि उत्सव- पटना

बिहार में शहरी समृद्धि उत्सव के तहत स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का पहला संस्करण भागीदारी के मामले में बहुत सफल रहा। राज्य के शहरी विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी) के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तीन दिवसीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 'के 22, 23 फरवरी, 24 फरवरी 2019 को समारोह का उद्घाटन किया। सिन्हा लाइब्रेरी ग्राउंड में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया

(नासवी) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के सहयोग से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा आयोजित किया गया। पटना की मेयर सीता साहू, विभाग के विशेष सचिव श्री संजय दयाल और संयुक्त सचिव श्री विवेकानंद झा भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के 100 से अधिक व्यंजनों को लोगों के लिए परोसा गया। 30 स्टालों में प्रसिद्ध और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तीन दिवसीय भोजन उत्सव में लगाए गए हैं

मंत्री मोहदाय ने स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए नासवी और FSSAI अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिए और अन्य शहरी स्थानीय निकायों में भी इसी तरह के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का आग्रह किया। नासवी ने तानसेन स्कूल ऑफ़ म्यूज़िक एंड आर्ट के सहयोग से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, बच्चों और कलाकारों द्वारा 50 से अधिक कार्यक्रम किए गए।

नेटफिक्स सीरिज पर नासवी का स्ट्रीट फूड

"दुनिया के सबसे जीवंत में से कुछ के लिए दर्शकों को लेने के लिए उद्देश्य से शहरों में स्ट्रीट फूड की समृद्ध संस्कृति का पता लगाने के लिए ग्लोब, "सह-निर्माता ब्रायन मैकगिन के एक ट्वीट के अनुसार। यह सीरिज एक सब एशिया के बारे में है और मैकगिन ने उस स्ट्रीट को छेड़ा भोजन सिंगापुर और भारत सहित कुल नौ देशों का दौरा करेगा | नासवी - स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो डालचंद की कहानी के रूप में विक्रेताओं को चित्रित किया गया है | यह पहली पंक्ति है जो नेटफ्लिक्स के लिए ट्रेलर का वर्णन करती है | आगामी श्रृंखला, स्ट्रीट फूड, 26 को शुरू की गई है अप्रैल, 2019 शो, टीम से आया है, शेफ्स टेबल के पीछे, पिछले महीने की घोषणा की गई थी, और है

Viewers will travel to Bangkok, Thailand; Osaka, Japan; Delhi, India; Yogyakarta, Indonesia; Chiayi, Taiwan; Seoul, South Korea; Ho Chi Minh City, Vietnam; Singapore; and Cebu, Philippines. In the roughly two-minute trailer, we see fiery sautées, noodles pulled and soups ladled, a blowtorch in action, and plenty of enthusiastic customers as various narrators weigh in on the meaning and importance of street food culture. One notes "people have been doing the same dish for 40, 50, 60 years–they never went to culinary school," while another calls it "a chaotic paradise of food."

नासवी अन्य नेटवर्क के साथ

❖ नेशनल एल्लाएंस ऑफ सोशल सेकुरिटी (नास)

नेशनल एल्लाएंस ऑफ सोशल सेकुरिटी (नास) नासवी द्वारा प्रोत्साहित एक अनौपचारिक संगठन है जिसमे भारत के 5 बड़े महत्वपूर्ण संगठन एक गठजोड़ के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलव्ध करवाने हेतु कार्यरत है| अभी इस मंच का समन्वय होम नेट साउथ एशिया के द्वारा किया जा रहा है| वर्तमान मे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित लेबर कोड के मुद्दे पर यह गठजोड़ असंगठित श्रमिकों के किए की मुख्य मांग करता है कि:-

- हमे श्रमिक के रूप मे पहचान व पंजीकरण किया जाय|
- हमें मातृत्व लाभ रु 60,000 दिये जाय (6 महीने न्यूनतम वेतन) |
- हमें प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन (न्यूनतम वेतन का 50%) का भुगतान करें|
- सभी लाभों के साथ हमें ईएसआई योजना से जोड़ें |
- विकृति और मृत्यु के स्थिति मे हमे 5, 00,000 रुपये की न्यूनतम क्षतिपूर्ति का भुगतान करें ।

उक्त मांगो के समर्थन मे राष्ट्र व्यापी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है | आप से अनुरोध है की आप इस अभियान मे भाग ले एवं 30 जुलाई तक हस्ताक्षरित पत्र नासवी कार्यालय मे भेजे| दिल्ली एवं पटना मे एक राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रस्तावित है| (प्रारूप संलग्न)

❖ सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल - एसडब्ल्यूजी

स्ट्रीटनेट से कुछ सदस्य संगठनों के बाहर निकलने, और स्ट्रीटनेट में शासन के तरीके के बारे में अन्य संबद्ध संगठनों से आने वाले नकारात्मक तथ्यो ने हमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर और बाहर स्व-नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नए संगठन का गठन करने के लिए प्रेरित किया है।

सेल्फ वर्कर्स ग्लोबल नामक इस नए संगठन में एनजीओ की नहीं, बल्कि पेशेवर एसोसिएशन के क़ानून हैं। पेशेवर संघों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, स्पेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क़ानूनके तहत उयाह पंजीकृत है ।

César García Arnal, con DNI 17725299G, actuando en su calidad de Secretario de la Comisión Ejecutiva y de la Asamblea fundacional de SELF-WORKERS GLOBAL-SWG,

CERTIFICA:

Que en la asamblea fundacional celebrada en Madrid, con fecha 18 de septiembre de 2018, se adoptaron, entre otros, los acuerdos que a continuación se relacionan.

ACUERDOS:

Primero.

Constituir una Asociación, al amparo del Artículo 22 de la Constitución y de conformidad con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, que se denominará SELF-WORKERS GLOBAL-SWG.

Segundo.

Aprobar los Estatutos por los que se va a regir la Asociación, que fueron leídos en el mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

Tercero.

Nombrar los miembros del órgano de gobierno y representación formado por

Presidente: Óscar Silva
Vicepresidente: Arbind Singh
Secretario General: César García

Cuarto.

Establecer la sede de la Asociación en calle Ciudad Real, 5, 28045. Madrid

Quinto.

Oscar Silva.

हमारा मुख्य उद्देश्य स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में अधिकारों का दावा करना है, नए स्वरोजगार स्थलों के निर्माण का समर्थन करना है, दुनिया भर में स्व-नियोजित श्रमिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को समरूप बनाना और विभिन्न सरकारों द्वारा हमारे सहयोगियों पर किए गए हमलों का खंडन करना है। हमारी ताकत पारदर्शिता और भागीदारी पर आधारित है। एसडब्ल्यूजी अपने प्रत्येक सदस्य संगठन को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हस्तक्षेप के आवाज देगा। हम चाहते हैं कि एसडब्ल्यूजी में ट्रेड यूनियन का चरित्र के साथ-साथ प्रतिनिधित्व, दावा और रक्षा विशेषता भी हों।

नासवी सदस्यता प्रोफाइल -2019

NASVI की वर्तमान सदस्यता असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, और मेघालय, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों के 758 संगठनों के 927483 सदस्यों की है।

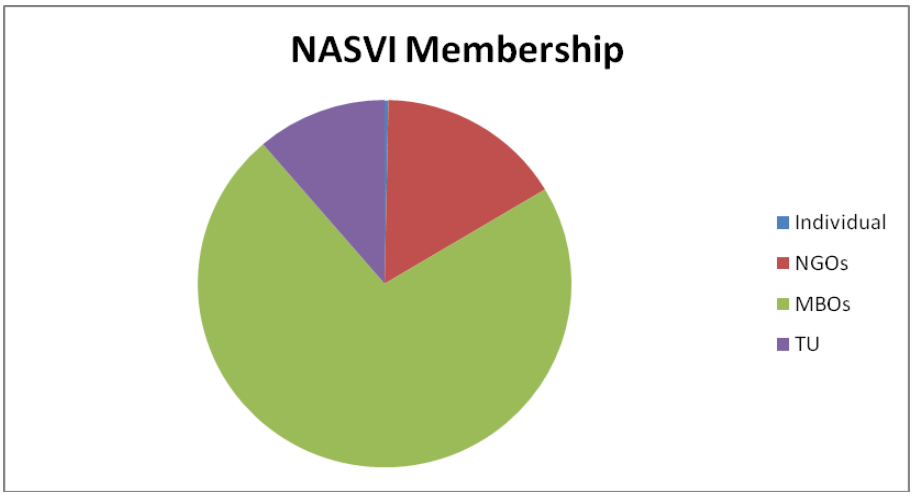

सदस्यता के प्रगति ग्राफ

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2016-17	2017-18	2018-19
Individual	1	13	1	1	1	2	4	9
NGOs	43	32	19	12	12	118	100	98
MBOs	54	45	23	19	27	59	455	499
TU	33	4	8	6	19	773	82	152
Total	131	94	51	38	59	952	641	758

नासवी के संविधान - ट्रेड यूनियनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBO), गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और वकीलों, शिक्षक, डॉक्टरों जैसे पेशेवरों के लिए सदस्यता प्रदान करता है जो स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दो से जुड़कर कार्य करते है| गत वर्ष वार्षिक आम सभा मे पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक सदस्य संगठन उस संगठन के प्रति विक्रेता सदस्य के आधार पर 1 रू वार्षिक योगदान देगा। गैर-सरकारी संगठन और व्यक्ति सदस्य सालाना 100रु सदस्यता शुल्क देंगे|

2006 के बाद से, नासवी धीरे-धीरे अपनी सदस्यता में एनजीओ की संख्या घटाने की प्रक्रिया शुरू कर रही थी और इसकी सदस्यता में एमबीओ और ट्रेड यूनियनों को बढ़ावा दे रही है । नासवी की सदस्यता की वृद्धि में क्रमिक वृद्धि दिखाई देती है। राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन आयोजन के लिए एक उत्साह था और 2004-2005 में उच्च सदस्यता परिलक्षित होता है। इसी तरह 2014 में अधिनियम लागू होने के बाद सदस्यता में बड़ी तेजी आई है | पूरे भारत में हमारे सहयोगियों की सदस्यता में वृद्धि हुई है।

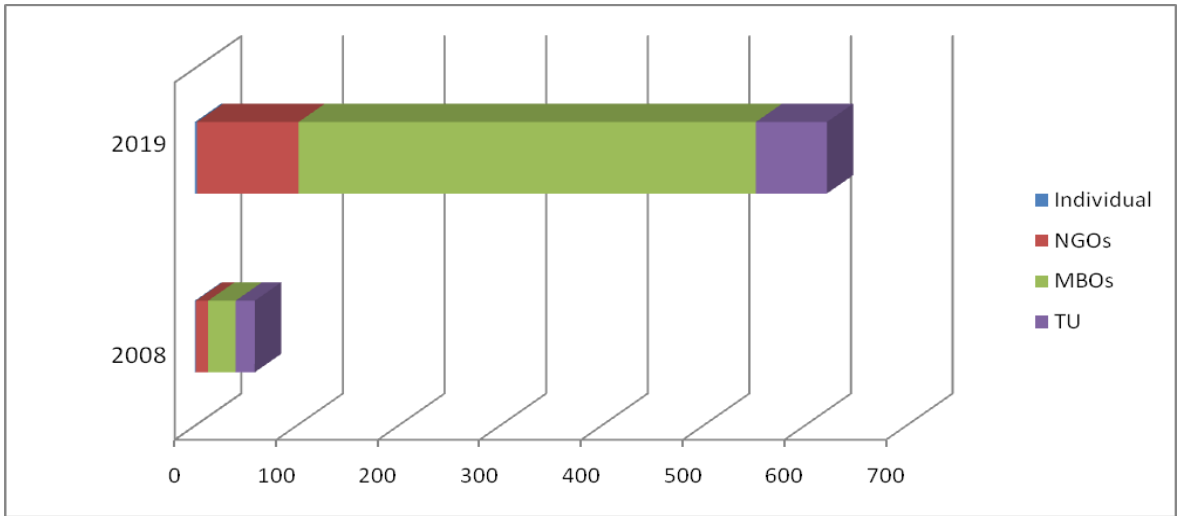

NASVI की पूरे भारत में 26 राज्यों में उपस्थिति है। नीचे दिया गया विस्तृत है -

State wise breakup of Memberships-2019			
S.No.	State	No. of org.	Member
1	Bihar	111	94617
2	Uttar Pradesh	123	33191
3	Madhya Pradesh	8	23248
4	Delhi	73	14275
5	Rajasthan	34	18350
6	Gujarat	10	10349
7	Maharashtra	11	13721
8	Manipur	2	1650
9	Meghalaya	1	813
10	Tripura	2	500
11	Orissa,	40	13525
12	Tamilnadu	135	588950
13	Andhra Pradesh	10	5564
14	Karnataka	60	46641
15	Kerala	13	4975
16	Haryana	1	130
17	Uttrakhand	16	3031
18	Punjab	11	4651
19	Jharkhand	2	1395
20	West Bengal	56	20262
21	Himachal Pradesh	1	50
22	Jammu & Kashmir	1	68
23	Telangana	26	16509
24	Assam	6	10005
25	GOA	4	437
26	Chhattisgarh	1	576
	Total	**758**	**927483**

कानून के 5 साल बाद : चुनौतिया

स्ट्रीट विक्रेता धैर्य से बाहर निकल रहे हैं: स्मार्ट सिटि परिकल्पना, राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन के फंड उपलब्ध, अधिनियम और कुछ जगहों पर अदालत के आदेश भी मिलने के बाद, वेंडर्स यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी कठिनाई का कारण कहां है। उनका संघर्ष शक्तिशाली विरोधी बलों के खिलाफ लंबा चल रहा है और वे अब इसे सहन करने में असमर्थ हैं। वे अपनी आजीविका के समाधान चाहते हैं।

केंद्रीय और राज्य सरकार की निरंतर भागीदारी: हम एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं क्योंकि उनकी भागीदारी के बिना अधिनियम को लागू करना संभव नहीं होगा। वे मुद्दों के बारे में जानते हैं लेकिन एक बिंदु से परे इसमें शामिल होने से बचते है । नगर निकाय राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और वे राज्य सरकार के केवल निर्देश पर ही काम करते हैं|

टाउन वेंडिंग मीटिंग्स: टाउन वेंडिंग समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती हैं। यहां तक कि निर्णय लेने पर भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। नगर प्राधिकरण अभी भी टीवीसी से परामर्श किए बिना निर्णय ले रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट का उल्लंघन कर रहा है।

वेंडोर्स के खिलाफ शहरी बल मजबूत हैं: मार्केट एसोसिएशन या निवासी कल्याण संगठन, अपने पैसो के बल पर विकास के विकास को रोकने मे उपयोग करने मे टक्कर लगी है। कई लोग अदालतों में जाते हैं और स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के उल्लेख किए बिना विक्रेताओं को बेदखल करने के लिए अदालत के आदेश प्राप्त करते हैं।

राज्य सरकार निविदा तंत्र दोषपूर्ण : यह हमारे जैसे संगठन की भागीदारी को बहुत मुश्किल बनाता है और जिन एजेंसियों को निविदा पर लिया जा रहा है, वे कई बार सड़क विक्रेता संगठन को उनके काम में बाधा के रूप में देखते हैं। कई नगर निकाय भाग लेने के लिए सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठनों की अनुमति नहीं देते हैं।

टीवीसी सदस्यों की क्षमता निर्माण: 2000 से अधिक टीवीसी गठित की गई हैं लेकिन उनकी क्षमता निर्माण नहीं हो रहा है और इस तरह वे अपनी जरूरतों को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं।

स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के आयोजन में आगे बढ़ना : यह अच्छा है कि हम इस चरण में आए हैं लेकिन आयोजन के लिए शहर स्तर पर और गहराई से राज्य स्तर पर समितियों के कामकाज के साथ और सुधार करना है।यदपि सरकार के द्वारा शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन एक अच्छा प्रयास है पर हम इसके लिए कितना तैयार है|

वेंडर्स को अभी भी इस अधिनियम से अनजान है: यह दुख की बात है कि अधिनियम के पारित होने के पाँच वर्षों के बावजूद कई स्ट्रीट वेंडोर्स और उनके संगठन इस अधिनियम से अनजान हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना 2019-2020

शिकायत निवारण तंत्र को परिचालित करने के लिए राज्य सरकार से पहल - स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है जो विक्रेताओं को नियमित अदालतों में जाने का प्रयास करता है। हालांकि चार साल बीत चुके हैं और इन्हें स्थापित नहीं किया गया है। अब समय आ गया है की उन्हें राज्यों में स्थापित किया जाय ।

राज्य स्तरीय समितियां सक्रिय भूमिका निभाने के लिए: जब तक राज्य स्तरीय समितियां सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तब तक पूरे देश में अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनकी भूमिका को तेज करने और जोर देने की जरूरत है। प्रत्येक राज्य समिति के पास व्हाट्सएप समूह होना है और राज्य स्तर पर एक स्थिति होनी चाहिए।

स्मार्ट सिटि एवं वेंडिंग कानून: स्मार्ट सिटि परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम मे कानून का पूर्ण उलंघन हो रहा है| इससे कैसे उबरा जाय|

जिला स्तर: जिला स्तर की समिति भी होनी चाहिए, जो जिला स्तर पर संघर्ष के लिए व्यक्ति को अधिक मान्यता और मजबूती देगा।

रेलवे विक्रेता: रेलवे विक्रेताओं के मुद्दों को उजागर करना और सरकार को कुछ नीतियों बनाने के लिए पहल करना |

पीआईएल पर नज़र : चूंकि राज्य स्तर पर कई पीआईएल कोर्ट मे दाखिल हो रहे हैं, इसलिए उन पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का प्रकाशन: टीवीसी, नेतृत्व और संगठन विकास पुस्तिका विकसित की गई है और अब इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए।

क्षमता निर्माण: राज्यों में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है |

वेंडर दिवस समारोह: हर साल की तरह, इस वर्ष भी 20 वीं जनवरी को विक्रेताओं दिवस के रूप में मनाया जाएगा

संकट में सहायता: यह अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि कुछ शहरों में संकट बढ़ रहा है।

राज्यों में अच्छे वकीलों की पहचान करें और शामिल करें: अधिक से अधिक संगठन न्यायालयों का सहारा ले हैं, राज्य स्तर पर अच्छे वकीलों की पहचान करके उनकी मदद करना आवश्यक है

स्ट्रीट फूड प्रोग्राम का विस्तार : इस कार्यक्रम में भारत के सभी शहरों में विस्तार करने की क्षमता है। कुछ प्रगति पहले ही हो चुकी है। रायपुर, भोपाल, त्रिवेंद्रम, कोचीन, मुंबई, पुणे, दिल्ली में प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। भुवनेश्वर और श्रीनगर में प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है।

स्ट्रीट फूड फेस्टिवल: पहले जैसा ही जारी रहेगा

स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए नए उद्यम लॉन्च करें: स्पेक्ट्रम को एक उद्यम के रूप में पहचाना गया है। विजन स्प्रिंग, कम लागत वाले चश्मे को बढ़ावा देने वाला एक सामाजिक उद्यम सहयोग के लिए संपर्क किया गया है

सामाजिक सुरक्षा: सरकार ने नए सामाजिक सुरक्षा संहिता की ओर धक्का दिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सड़क विक्रेताओं और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करने पर काम करते हैं |

सदस्यता एमआईएस अपडेट करें: निष्क्रिय सदस्यों को हटाने के बाद मिशॉल्ड अपलोड किया जाएगा, जिसे हम अनावश्यक रूप से आगे लेते रहते हैं।

सदस्यता का विस्तार: एक जोड़ एक के सिद्धान्त पर मौजूदा संगठनो को कार्य करना होगा|

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म: NASVI को डिजिटल साक्षरता और भुगतान की स्वीकृति के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर जोर देना चाहिए

सदस्यों के साथ बेहतर संचार: यह विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होना चाहिए |

राज्य स्तर पर मीडिया के साथ जुड़ाव: हमें राज्य स्तर पर मीडिया को अधिक कुशलतापूर्वक संलग्न करने की आवश्यकता है।

स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के क्रियानवायन पर एक फिल्म: एक फिल्म जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट और उसके कार्यान्वयन और कठिनाइयों के पूरे मैदान को पकड़ती है, बहुत उपयोगी होगी

एक वैश्विक निकाय: सेल्फ वोर्कर ग्लोबल को एशिया क्षेत्र मे आगे बढ़ाना|